[Secretary General]

1982, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 27th March, 1982.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill."

(2)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Kerala Appropriation Bill, 1982, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 27th March, 1982.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill."

(3)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Assam Appropriation (Vote on Account) Bill, 1982, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 27th March, 1982.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill."

(4)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Assam Appropriation Bill, 1982, as passed by Lok Sabha, at its sitting held on the 27th March, 1982.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill."

Sir, I lay a copy each of the Bills on the Table of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (DR RAFIQ ZAKARIA): The House stands adjourned till 2 p.m.

The House then adjourned for lunch at two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at three minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Dinesh Goswami)** in the Chair.

(I) MOTION SEEKING REVOCATION OF THE PROCLAMATION ISSUED BY THE PRESIDENT ON THE 17TH MARCH, 1982, IN RELATION TO THE STATE OF KERALA

(II) STATUTORY RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF THE PROCLAMATION ISSUED BY THE PRESIDENT ON THE 17TH MARCH, 1982, IN RELATION TO THE STATE OF KERALA

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Bihar): Sir, I beg to move the following motion:

"That this House recommends to the President that the Proclamation issued by the President on the 17th March, 1982 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Kerala be revoked."

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रोक्लेमेशन हुआ राष्ट्रपति का और जिससे कि राष्ट्रपति शासन वहां लागू किया गया उसका मैं पूरी ताकत के साथ विरोध करता हूं। मैं ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि सारा सदन इसका विरोध करेगा। क्योंकि यह कदम जो केन्द्रीय सरकार ने उठाया है वह हमारा संविधान जो है उसकी स्पीरिट के ऊपर एकदम कुठाराघात किया है। जो जनतंत्र का चीर-हरण वहां हुआ है उस पर मैं जरा बाद में कहूंगा। वहां पर स्पीकर ने सात-सात बार वोट दे कर मुर्दे को जिलाने की कोशिश की है और साथ ही साथ गवर्नर वहां का जो है उसने भी अपनी अक्लमंदी का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में जो होना चाहिये और एक रूलिंग पार्टी को टूल के रूप में काम किया। and not as a vanguard of the democratic framework under the Constitution itself.

उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह कदम उठाया है आर्टिकल 356 आफ दी कांस्टीट्यूशन के तहत, यह आर्टिकल

क्या है । यह संविधान हमारे हाथ में है । लेकिन उसके पहले आर्टिकल 355 है जो थोड़ी प्रिप्रेटरी ग्राउंड जिसको कहते हैं वह 356 के लिए है। 356 का मतलब, उसकी शुरूआत में है कि यदि एक्सटर्नल एग्रेशन हो और इन्टर्नल डिस्टरबेंस हो तब राष्ट्रपति किसी इलाके की या सारे देश की ताकत अपने हाथ में ले सकता है और उसी आधार पर वह 356 लिया गया है । मैं पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता हूं क्योंकि आप जानते हैं कि 356 में क्या है । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह धारा 356 जब आखिरी रूप में बन रही थी, खत्म हो रही थी तो संविधान के, फादर आफ द इंडियन कांस्टीट्यूशन, डाक्टर अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा सुनिये । उन्होंने कहा कि यह प्राविजन 356 में जो है :

"It will never be called into operation and would remain a dead letter. If at all, they are invoked, I hope the President who is endowed with these powers shall take proper precaution before actually suspending the administration of the provinces, as the States used to be called."

फादर आफ द इंडियन कांस्टीट्यूशन डाक्टर अम्बेडकर ने कहा कि यह धारा बाहरी हमलों और अन्दरूनी डिस्टरबेंस, जिसमें कोई उपद्रव हो, आम रिबेलियन, केवल उन्हीं के लिए इस्तेमाल की जायेगी और कभी नहीं । यह डेड लेटर रहेगा । लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार के मातहत यानी जब से संविधान लागू हुआ अब तक 68 टाईम्स इसका उपयोग हुआ । केरल में 67 और आसाम में 68 टाईम्स । लेकिन केरल पर सबसे ज्यादा प्रेजीडेंट रूल 9 टाईम्स हुआ । मेरे पास सारी लिस्ट है कि कहां तक कितने दफे हुआ । सबसे ज्यादा हाईएस्ट है केरल में और दिन के हिसाब से 616 दिन, यह इस किताब में है, बहुत अच्छा दिया है, 'असेम्बलीज इलेक्शन्स बाई मीरचंदानी, लाईब्रेरी की किताब है, सारा इसमें दिया है कि कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन हुआ है, जब से संविधान लागू हुआ । पांडिचेरी को हम छोड़ देते हैं उसका अपना स्पेशल केस रहा है. उसमें जाने की जरूरत नहीं है । तो हाईएस्ट है केरल में 1616 दिन, वहां अब तक इतने दिन राष्ट्रपति का शासन रहा, उसी तरह से औरों में है । टाईम्स में 9 टाईम्स हाईएस्ट है केरल । केरल पर इस सरकार का खास गुस्सा है शुरू से । इसलिए कि केरल की जनता संघर्षशील है, केरल की जनता कान्सस है, राजनीतिक तौर पर, सजग है और केरल की जनता डिडीकेटिड है समाजवाद के लिए । यही गुस्सा उपसभाध्यक्ष महोदय इनका है । ऐतिहासिक रूप में थोड़ा सा नक्शा और दे देना चाहता हूं । यह गुस्सा शुरू कैसे हुआ मंत्री जी ? गुस्सा शुरू हुआ जब भारत के इतिहास में इन जनरल और केरल के इतिहास में इन पार्टीक्यूलर 1952 में सोशलिस्ट सरकार का उदय हुआ । आई ब्रोज का उठना जिसको कहते है, जब सोशलिस्ट सरकार बनी 52 में तो उसी समय से केन्द्रीय सरकार की आई ब्रोज तनने लग गयी । यह तब शुरू हुआ, क्या पोलिटिकल पाइरेसी, आप जानते हैं, पाइरेट क्या होता है । पोट्टम थानु पिल्ले को तड़फाया गया, बाद में लाट साहब बनाये गये, वगैरह, वगैरह, यह सब अलग कहानी है उसमें जाने की जरूरत नहीं है । तो पोलिटिकल पाइरेसी से केरल को डील करने की शुरूआत हुई । लेकिन उससे बड़ी डीलिंग कब हुई ? आप कहेंगे वह छोड़िये बहुत पुराना है । तो अब मैं इन्हीं के कार्य से, समय से आता हूं, जब मौजूदा प्रधान मंत्री, हिन्दुस्तान के राजनीतिक क्षितिज पर उदय होती हैं, कांग्रेस प्रेजीडेंट के रूप में 1957 में, तब से । उपसभाध्यक्ष

[Shri Shiva Chandra Jha]

महोदय, सही सलामत नम्बूदरीपाद की सरकार, को जानदार सरकार को, सांस लेने वाली सरकार को उस वक्त की कांग्रेस प्रेजीडेंट, मौजूदा प्रधान मंत्री जी ने घसीट कर सड़क पर ला दिया । कुछ उसी तरह से घसीट करके जिस तरह से मगध के शासन सिंहासन से नंद राजा को चाणक्य ने घसीट करके पाटलिपुत्र की सड़कों पर फेंक दिया । नम्बूदरीपाद दौड़ा हुआ कुल्लू-मनाली जाता है । वहां पं० जवाहरलाल नेहरू विश्राम कर रहे थे । पंडित जी को सब बातें बताता है । पंडित जी ने तमाम बातें सुनीं और सुनने के बाद पंडित जी ने क्या कहा नम्बूदरीपाद को--पंडित जी ने वही कहा, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्मराज युधिष्ठर ने कहा--

"अश्वत्थामा हतो, नरो वा कुंजरोवा"

पंडित जी ने कहा कि--"अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरोवा"--यह कह दिया और वह पहा सलामत सरकार को, कांग्रेस की प्रेजीडेंट श्रीमती इन्दिरा गांधी ने त्रिवेन्द्रम की सड़कों पर घसीट दिया । यह पहला स्वाद था, प्रेजीडेंट रूल वहां लागू हो गया । यह पहला स्वाद था मौजूदा प्रधान मंत्री का कि ओ हो बहुत टेस्टफुल है प्रजीडेंट रूल ।

उसके बाद की कहानी सुनिये । जब एक बार स्वाद लग जाता है, तब भूख कितनी बढ़ जाती है, उसको मैं सुनाना चाहता हूं । 1966 से लेकर के 1977, जब तक लोकनायक का तूफान नहीं आया जनक्रान्ति का, इन ग्यारह सालों में जब इनका काल था प्रधान मंत्री के रूप में, इक्तीस बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया । यह सब के सब आंकड़े हैं, इक्तीस बार ।

लेकिन वह भी जरा नक्शा साफ हो जाएगा । यदि 1966 से पहले का काल ले लें, 1950 से लेकर के 1966 तक, सोलह साल में जब पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का काल था, उसमें सिर्फ आठ बार, यानी यदि एवरेज बिठा देते हैं, तो दो साल में एक बार, यदा-कदा कहीं-कहीं और कुछ बातें क्षम्य थीं उन लोगों के टाइम में लागू करने के लिए । लेकिन जब यह स्वाद लगा कांग्रेस के प्रेजीडेंट के रूप में और जब इनके हाथ में बागडोर आई दिल्ली की, तब तो भूख और बढ़ने लग गई और ग्यारह साल में इक्तीस बार प्रेजीडेंट रूल 1965-66 से लागू हो गया । सब पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस, डिफैक्शंस को तड़पाना, लाना और अपने फैक्शन को गद्दी पर बिठाना, इसलिए किया, यानी पॉलिटिकल मोटिवेशन भी चलते हो हैं ।

श्रीमन्, तो यह हुआ । अब जब यह हट गई और 1980 में आई और 1980 में जब आई, तब से देखिये वही धंधा फिर शुरू हुआ है । पहले कोशिश थी कि हरियाणा से भजन लाल जैसे को तड़पा करके लाओ, सरकार को गिरा करके लाओ प्रेजीडेंट रूल । कुछ थोड़ा-सा सफल हुए, लेकिन उस सफलता से संतुष्ट नहीं थे और आपको याद है कि इसी सदन में राष्ट्रपति के शासन पर अमैंडमेंट पर हम लोगों ने हरा दिया था जब इनका बहुमत नहीं था, और जब केन्द्र से निकलो, तो फुफकारा मारते हुए, जो मुझ को सुनने में आया ।

अब इन लोगों ने मेरा रास्ता साफ कर दिया है और नौ राज्यों की जो असेम्बलीज थीं, सही सलामत--जनता वालों के हाथ में या इनके हाथ में, सब को एक तरफ से गिराने लग गईं ।

श्रीमन्, तो इनका यह सिलसिला चलता रहा--(समय की घंटी)--गिराने लगीं । इनके काल में जैसे कि मैंने कहा कि इक्तीस बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ ।

यदि आप एवरेज बिठायेंगे, तो हर चार-पांच महीने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। पंडित जवाहरलाल और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में दो साल में एक दफा और इनके काल में चार-पांच महीने पर वह नवजात शिशु, राष्ट्रपति शासन को गलत तरीके से जन्म दिया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह प्रापेंसिटी, एक आथोरिटेरियन प्रापेंसिटी बहुत जबर्दस्त है। मंत्री महोदय, आप तो कल और परसों हिटलर होने का सपना देखने लगे हैं लेकिन आपसे पहले यह उनका सपना देखते रहे हैं, 1967 से। आप तो कल से हिटलर बनने वाले हैं लेकिन इनका आज से नहीं, '57 से पहले सिलसिला जारी है, वह चल रहा है ...(समय की घंटी)...... इसीलिए केरल में जो हो रहा है उसी चेन में वह एक कदम है। अब केरल की मौजूदा परिस्थिति क्या है? केरल की परिस्थिति में उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि वह. प्रशासन राष्ट्रपति का लागू करना होता, लागू करने की जरूरत थी, तो यह करुणाकरन की सरकार जब बन गई थी उसी वक्त लागू करना चाहिए था। इन्सानियत का जनतंत्र का तकाजा था कि उसी वक्त लागू करना था क्योंकि जो डिफेक्शन से सरकार बनाने गए थे उनको अनुमति देना संविधान से खिलवाड़ करना होगा। लेकिन नहीं, वह पासा फेंका गया और पासा फेंका के बाद कहने की जरूरत नहीं है क्या हुआ, हमने देखा है कई जगह ऐसी सरकारें मर चुकी है। सत्तर इधर, सत्तर उधर, फ्लोर पर जब वोटी-वोटी होती है तो स्पीकर अपने वोट से उस मुर्दे को जिलाता है। सात-सात बार वोट देकर मुर्दे को जिलाया। स्पीकर, जिसको कांस्टीट्यूशनल हैड कहते हैं वह यहां तक जाने के लिए तैयार होता है। क्या हमारे जनतंत्र पर यह हमला नहीं, जिस कांस्टीट्यूशन की सैंकटिटी को स्पीकर कायम रखता है....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now please conclude.

श्री शिव चन्द्र झा : क्या यह उस पर प्रहार नहीं? उनकी प्रापेंसिटी, उनकी भूख तो मैंने बताया, बहुत जबर्दस्त है।

गवर्नर की बात ले लीजिए। वे महिला हैं। गवर्नर का मतलब सिर्फ रबर स्टाम्प नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति को देखने के लिए उसको आंख होती है। संविधान मानता है कि यदि परिस्थितियां ऐसी हों तो अपने विवेक को इस्तेमाल करो। रूलिंग पार्टी का टूल मत बनो। तो गवर्नर को चाहिए था कि संविधान के मुताबिक कदम उठाने के लिए सलाह देते। लेकिन उन्होंने एक भी सलाह दी आपको। अब जब करुणाकरन सरकार का एक आदमी हट जाता है यह कह कर कि अब हमारे वोट से सरकार नहीं रहेगी, तब रिकमेण्ड करती हैं कि तुरंत लागू कर दिया जाए राष्ट्रपति शासन। इसी लिए केरल में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वह भारत के संविधान के ख़िलाफ पोलिटिकल मोटिवेशन से ओत-प्रोत होकर किया गया है। जनतांत्रिक पद्धति के अंदर वहां के स्पीकर ने सात-सात बार वोट देकर मुर्दे को जिंदा रखा। इस तरह से गवर्नर को एक हायरलिंग और टूल के रूप में एपौंइट करना यह हमारे संविधान निर्माताओं, डा० अम्बेडकर और पं० जवाहरलाल नेहरू की मन्शा के ख़िलाफ है।

मंत्री जी, हम लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आप वही हैं जिन्होंने मसूरी के प्रौबेशनर के लिए रिफार्मेटिव मेज़र लेने की

[श्री शिव चन्द्र झा]

बात कही थी और हम लोगों के आवाज उठाने पर ठीक रास्ता पकड़ा और उसको हटाया गया। क्या आप वही हैं? इसीलिए एक गलत काम जो उठाया गया है, आप हिटलर बनने की तमन्ना छोड़ दें। आप वाहे गुरू के नाम से इस प्रोक्लेमेशन को वापस कर लें नहीं तो सारे देश में वाहे गुरु के नाम से खड्ग तैयार है। डिविजन में हम इसका विरोध करेंगे आखिरी दम तक। धन्यवाद।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (GIANI ZAIL SINGH): Sir, I beg to move the following Resolution:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 17th March, 1982, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Kerala."

वाइस चेयरमैन साहब, मेरे से पहले जो रिजोल्यूशन मूव किया गया आप जानते हैं कि उस में चाहा गया है कि यह प्रोक्लेमेशन वापस लिया जाय और प्रेसिडेंट्स रूल रिवोक किया जाय। मैं इस की सारी रिप्लाई तो आखिर में दूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात जरूर कहूंगा। आनरेबिल झा साहब ने ऐसे तकरीर की जैसे कोई मिनिस्टर करता है बच-बच कर।

एक माननीय सदस्य : वे आ रहे हैं।

ज्ञानी जैल सिंह : इधर ही आ कर मिलेगी।

श्री शिव चन्द्र झा : तूफान आ रहा है।

ज्ञानी जैल सिंह : तूफान पहले आप को उठायेगा, आने दो। उन्होंने बड़े आश्चर्य की बात की। उन्होंने बताया कि अम्बेडकर ने यह कहा---उस में तो मैं नहीं जाता, फिर गिनती बता दी, वह ठीक है, कितनी बार हुआ वह बिल्कुल ठीक है, किस रियासत में हुआ वह बिलकुल ठीक है। इसमें हमारा विरोध नहीं है। उन को एतराज है कि पहले क्यों नहीं किया, हम ने देर कर दी। अगर उन का यही मतलब है तो मैं मानता हूं कि देर हो गयी, इसे पहले कर देना चाहिए था। इस लिए हमारा कोई झगड़ा नहीं रहता। लेकिन रिजोल्यूशन और मूव किया है कि रिवोक कर दो। इतने लर्नेड पर्सन---प्रेसिडेंट्स रूल हो गया, वहां की विधान सभा भंग हो गयी, अब इस को रिवोक कर दें तो क्या करें यह बताया नहीं। इस को रिवोक भी कर दें, लेकिन विधान सभा तो दुबारा जीवित नहीं हो सकती। उतनी देर जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक आप का क्या सुझाव है?

श्री शिव चन्द्र झा : [एक मौका विरोधियों को देते।

ज्ञानी जैल सिंह : बीच में मत टोकिये, अपनी बात दूसरे साथी के कान में कह दीजिए, वह कह देगा। मेरी बात गलत होगी तो मैं मान लूंगा।

अब वह कहते हैं कि हम डिक्टेटराना तरीके से चलते हैं। यह बिलकुल निराधार है। हम तो जम्हूरियत के बुनियादी उसूलों के मुताबिक चलते हैं। वहां पर जम्हूरियत बदनाम हो रही थी। मैं मानता हूं कि केरल के लोग बहुत समझदार हैं, दूरंदेश हैं, नीतिवान हैं, लेकिन वहां इतनी बार प्रेसिडेंट्स रूल करना पड़ा। इस मामले में वह पहले नम्बर की स्टेट है कि वहां 12 के करीब पोलिटिकल पार्टीज हैं। इन में से 7–8 ऐसी हैं जिन के नाम एक ही हैं और आगे जा कर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सारी बातों के होते हुए उन की तकरीर से तो यही साबित होता है कि वहां प्रेसिडेंट्स रूल के सिवा कोई चारा नही था।

तीसरी बात उन्होंने कही कि गवर्नर को रूलिंग पार्टी का टूल नहीं बनना चाहिए। बिलकुल सही बात है। वह श्रीमती जी इतने ऊंचे दर्जे की गवर्नर है कि वह किसी का टूल नहीं बन सकतीं, खुद अपने ब्रेन से सोच कर

फैसला करती हैं। उन्होंने हम को मशविरा नहीं भेजा कि विधान सभा को भंग कर दो। उन्होंने वही कर दिया और अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया। केरल की हालत को वह अच्छी तरह जानती हैं, नयी गवर्नर नहीं हैं, वह गवर्नर बनी थीं जब हमारे महानुभाव मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे और चौधरी साहब और बाबू जगजीवन राम डिपुटी प्राइम मिनिस्टर थे। तीन बड़े बुजर्गों ने छांट की और ऐसी शख्सियत को वहां गवर्नर बनाया, जो बिल्कुल बिना किसी लिहाज के, बिना किसी डर के, जो उस की आत्मा की आवाज है, कांस्टीट्यूशन के मुताबिक उस में उन की क्या ड्यूटी है उस ने उस की पूर्ति की। इस लिए टूल कहना अच्छा नहीं है और झा साहब के शोभा नहीं देता। बड़े शरीफ आदमी हैं। जब किसी की मुखालिफत भी करनी हो तो जरा शराफत से, डिगनीफाइड तरीके से करनी चाहिए। ऐसा शब्द गवर्नर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टूल और फूल करीब एक जैसे होते हैं जिनको जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि वह आइन्दा यह नहीं कहेंगे।

एक बात उन्होंने और कही और वह बात तो खत्म हो गयी वह प्रोबेशनर का मामला था। रिफार्मेटिव मेजर्स लेने थे। मैं मान लेता हूं कि उस वक्त आप की बात रह गयी और उसे मान कर पहला जो हमारा कुछ कमजोर फैसला था उस को बाद में हम ने सख्त कर दिया। आप ने उस की मिसाल दी। वहां आप की बात हम ने मान ली, लेकिन यहां अगर मान लें तो करें क्या। उसको पहले नरम सजा दी थी बाद में सजा सख्त कर दी। वह बात खत्म हो गयी। आप मुझे राय देते हैं कि हिटलर के रास्ते पर न चलूं। मैं मान लेता हूं, लेकिन यह तो बताइये कि करूं क्या।

श्री शिव चन्द्र झा : वहां चुनाव कराइये।

ज्ञानी जैल सिंह : रिवोक करने से असेम्बली कैसे चलेगी। जब तक वहां कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है तो वहां का राज कैसे चलेगा? या तो वह इस रेजोल्यूशन को मूव न करते, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो मालूम होता है कि उन के ख्यालों के मुताबिक यह रेजोल्यूशन नहीं बना है। खैर यह तो अपोजीशन का काम था, उन्होंने कर दिया। आप को यह कहना चाहिए कि सरकार के फैसले के साथ हम इत्तफाक नहीं करते, मगर कोई रास्ता नहीं है इसलिये हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी-जल्दी हो सके वहां एलेक्शन करवाये जायं, और डेमोक्रेटिक सेट अप वहां इस्टेबलिश किया जाय। यह बात अपोजीशन की बनती है। मेरे कहने पर वह नहीं मानेंगे, लेकिन मैं ने तो रीजनेबिल बात कही है और उन की बात तो मैं मान ही नही सकता। वह मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हम को चलना है।

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The Motion and the Statutory Resolution are open for discussion. The Business Advisory Committee has fixed two hours for these and I think we have already covered half an hour. So I would request Members to keep within the time-limit. Therefore, Mr. Madhavan, your time is only six minutes.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): It may be his parting speech. He may be given more time.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Prime Minister make a statement on her visit?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We have not received any intimation as yet. Yes, Mr. Madhavan.

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): Sir, I think it is my duty to support

[Shri K. K. Madhavan]

the Motion and oppose the Statutory Resolution. You may recall that on earlier occasions, when the Governor of Kerala recommended suspended animation of the Kerala Legislative Assembly—I think on the 21st October—the matter was subsequently placed on the floor of this House, when also I had to oppose it. This time it is surprising to see that the Governor has exercised her powers under Article 174, not under 356. Article 174 has got...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): That is known, Mr. Madhavan. And once a politician leaves his seat, it is very difficult to get it back.

SHRI K. K. MADHAVAN: Article 174 gives only a limited power to the Governor, only of a casual nature, that is not to be exercised on occasions like this. Article 174 simply gives an ordinary type of power for prorogation or dissolution in the routine nature of business. In this particular case it is not a routine business. It is something else. Actually the competent body to dissolve the Assembly on this occasion, on an occasion like this, is the Rashtrapathi and not the Governor. Why the Governor chose it herself to dissolve the Assembly is a very important question. This dissolution comes in the wake of the so-called defection of one Member, Mr. Lonappan Nambadan, who was elected opposing the present Government's major parties in the last election in 1980. Mr. Lonappan Nambadan was elected on the ticket of the Left United Front and subsequenty when his party withdrew support to the LDF Government, only in strict obedience to the discipline of the party he agreed to quit. But now he has found that he had gone on a wrong line. He has retraced his steps. That is all. It is not an ordinary kind of defection. He thinks that he was elected as part and parcel of the Left United Front. It was a mistake that he had left it. Now he has come back. That is the position.

SHRI B. V. ABDULLA KOYA (Kerala): What about those two Janata members who have joined the Marxist group?

SHRI K. K. MADHAVAN: I am pointing out the changed character of the Government—the Government that has fallen. That Government had never had a majority. It had never proved its majority. The Government headed by Mr. Karunakaran entered the House after January 1980 elections with his 17 Members. It was his party which was heading the Government that has fallen now. He was sworn in on the 29th December. The previous Government resigned on the 20th October. Because of their resignation, the first declaration of the President's rule came. It was revoked on the 28th December to facilidate Mr. Karunakaran to become the Chief Minister with 17 Members in his party. Of course, by regular methods of unabashed defection and incentives to defection, he made all attempts to make a majority. But he did not get a majority still. When he was asked to take up reins of Government and to form the Government, he had only 67 persons in a house of 141 members. Out of these, 140 were elected members and one nominated member. Together with one nominated member, the former Chief Minister had only 67 members. Four members joined him later. One Mr. K. K. Nair had declared that he would not decide anything before the crucial day of trial of strength on the floor of the House.

AN HON. MEMBER: Are you sure?

SHRI K. K. MADHAVAN: Yes; it was published in the newspapers.

Then again, three members from the Janata Party (dissident) had not joined them. They did not promise support. They joined or supported only on the day of the trial of strength, not earlier. Thus on the 28th December, the so-called Chief Minister had no majority in the House. He had only 67 members with

him in a house of 141 members. One of his members was elected to the Speaker's position. He had with him 67 members plus the Speaker. That is all. As against that, in the opposition side there were 70 members. Now, here is a curious position where the Government side had with them 69 elected members on the floor of the House and one nomnated member. Together they had 70 members whereas the opposition had 70 full-fledged elected members. That itself was indicative of the fact that in terms of numerical strength of elected members, the opposition was much more weighty. So, to get the support of Shri K. K. Nair, who hails from Quilon district, the creation of a new district, revenue district, was offered. Sir, is it not unholy to tempt a member to the Government side, to get the support of a person, by offering a new district of his linking? That is one thing. I do not want to say anything about the bait that might have been extended to the three Janata dissidents. It was clearly by such methods of unholy defections that the party which was led by a leader with only 17 members swelled its ranks to 71; from 17 to 71.

SHRI HAREKRISHNA MALLICK: Just the reverse!

SHRI K. K. MADHAVAN: Yes. The march from 17 members to 71 members was beset with all sorts of unholy methods. So, that Ministry fell on the 15th, the Ministry which was the creation of all sorts of defections put together.

Again, there is the notorious series of casting votes exercised by the Speaker on the day of passing the Motion of Thank on the Governor's Address. This is something extraordinary. The Speaker had to exercise his casting vote seven times on the same day! So, that Government was sustained by the casting vote of the Speaker only and nothing else; of course, even with the support of a Nominated member also. (*Time bell rings*) What is this Government? This Government was consisting of or composed of all sorts of reactionary elements, all sorts of conservative elements. One of the parties in NDP. What is it? They staged a dharna, went on direct action, just in front of the State Public Service Commission.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I do not think that we are concerned with all these things. I don't think that we are concerned with questions as to how the Government was formed there or what it is composed of. So, let us avoid those things now.

SHRI K. K. MADHAVAN: But we are concerned with those things and I will tell you how. For the first time in the history of Kerala, there was a Government in which there was no one from the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe as Minister. That is my point. Of all these eight parties, no party was a one-member party. And those parties agreed together not to have a Harijan in the Cabinet or the Council of Ministers. What is the reply that the Home Minister has to give to that? For the first time, the Harijans were kept away from the Cabinet (*Time bell rings*) Yet, they say that this is a progressive Government. This is what some people say. So, this is the position. All sorts of reactionary elements collected together, attracted by all sorts of baits and all sorts of defection methods, to create a party or a United Front which, according to the Governor herself, had only 41 members. It is according to her own report. The United Democratic Front, which had only 41 members even according to the report of the Governor, swelled its number, owing to unholy methods, to 71 and the Governor's report itself mentions this. Kindly permit me to read out from the report. It says:—

"On the 15th March 1982. Shri Nambadan, belonging to the Kerala Congress (Mani Group) along with the constituents of the UDF met me

[Shri K. K. Madhavan]

and informed me in writing of his resignation from the Kerala Congress and withdrew suppor from the Karunakaran Ministry. As a result, the strength of the UDF has been reduced to 69 excluding the Speaker in a House of 141. Shri Karunakaran had met me at 11 a.m. today and handed over the resignation of the Council of Ministers headed by him. He has communicated the recommendation of his Council of Ministers that the State Legislature should be dissolved."

So, this is the most important point. The Governor herself admits that the Ministry has been reduced to a minority in the House and that very Governor says that she has accepted the recommendation of this minority Council of Ministers. The Chief Minister was leading the minority United Democratic Front Government. That is a contradiction. The Governor admits that the United Democratic Fron.'s government was a minority Government and that it has lost its majority. The same Governor says that on the recommendation of the outgoing Chief Minister who had lost majority, and on accepting the advice of that Chief Minister, she dissolves the Assembly. That is the point. How can the Governor accept the recommendation of a Chief Minister who had lost majority in the Assembly? It is unconstitutional, illegal and immoral because the Chief Minister had lost majority.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You have made your point Mr. Madhavan. I have given you more than double of your time.

SHRI K. K. MADHAVAN: Mr. Karunakaran was given two months to win over other Members and to bait Members in the opposition so that he could get their support by defection. For ten weeks, the Assembly was kept under suspended animation. When one single Member leaves the United Democratic Front government and converts the United Democratic Front Government into a minority, the next day the Assembly is dissolved. Why do you have this double standard? It is because there was the election to this House. I had filed my nomination on the 17th which was the last day for filing nomination. I had filed the nomination at 42.30 P. M. when the Asembly had not been dissolved. I went there for scrutiny on 18th. I was just sitting with the Returning Officer. I demanded of him that scrutiny is a process which cannot be avoided and that he has to finish scrutiny work. He did not do anything. I insisted that scrutiny had to be done. What is the law? The election begins with the notification and ends with the declaration of results. Election is a long process which consists of so many stages. One of the stages is scruitiny. At that time I was sitting there and the Assembly had not been dissolved. There was no information from the Election Commission. The Returning Officer told me that he was waiting for some information from the Election Officer. I told him that the Election Commission's information could not have retrospective effect. I am a valid candidate. I do not know under what rule my nomination has been cancelled. I may be permitted to point out that this Central Government dictates and the Governor had to play the role of a cat's paw using all sorts of nasty methods and unholy methods just to keep the ruling party in the Centre in power in Kerala also. This is what a gubernatorial office has been degraded to. Thank you.

*SHRI M. S. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu): Sir, I rise to support the Statutory Resolution moved by the hon. Home Minister and to oppose the Motion moved by Shri Jha.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I don't think the English translation is coming.

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

SHRI M. S. RAMACHANDRAN: In that case, I will switch over to English. If the interpretation is not available, then I will switch over to English.

श्री जैल सिंह : तमिल में बोलना चाहिए ।

DR. (SHRIMATI) SATHIAVANI MUTHU (Tamil Nadu): You speak in Tamil.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): There must be something wrong. You can go ahead. *(Interruptions)*

श्री जैल सिंह : यह परम्परा गलत है, तामिल में बोलना चाहिए ।

SHRI M. S. RAMACHANDRAN: Sir, with your kind permission, I will switch over to English.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I support the Resolution moved by the hon. Home Minister and oppose the Motion moved by the hon. Member, Shri Shiva Chandra Jha.

Sir, it has been mentioned by my hon'ble colleague on the other side that unfortunately for Kerala, this is the ninth time that the State was brought under the President's Rule. Sir, it is very unfortunate and none of us is happy that the State Assembly should be dissolved and the President should take the administrative powers of any State in our country. But the fact cannot be disputed by anybody that there was a constitutional crisis on the 17th March, 1982 by the resignation of one of the hon Members of the Kerala Legislature and thereby the Government lost its majority. And on the very same day, unlike his predecessor, Mr. Karunakaran tendered his resignation. Even after the Congress (S) which was the largest party in the so-called United Front came out of the United Front wanted to continue. Even after Mr. Antony's going out of their front, they wanted to continue with the strength of the several other mushroom parties, and they were not willing to resign. But we had the guts, we had the democratic sense of responsibility and on the very day when one of our Members left our Party, we submitted our resignation. Not only that, Sir. . . .

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: That is because you lost the majority.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Mallick, I don't understand these interruptions. I don't think it is fair on your part. You just stand up and interrupt. It is not fair. I must take strong exception to it. Mr. Ramachandran, you please go on.

SHRI M. S. RAMACHANDRAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, during the previous Proclamation, we were accused of keeping the Assembly in suspended animation. Who was responsible for that? The then outgoing Chief Minister Mr. Nayanar, simply tendered his resignation. He did not make any recommendation as to the fate of the Assembly then. But this time, when Mr. Karunakaran tendered his resignation, he realised his sense of responsibility to the State, to the people of Kerala and he made a recommendation to the Governor that the Assembly should be dissolved. Sir, I am surprised what really my friends on the other side want. During the previous Proclamation when the Assembly was kept under suspended animation, they were accusing us of trying to have horse-trading, trying to have an alternative Government. We were accused that we were committing the biggest sin in the world. But, what are they asking today? The Assembly should not have been dissolved. An attempt should have been made to find out the source of alternative Government. Mr. Nayanar did not make any such recommendation either at the time of his resignation or in his resignation because they did not know what to do. To go out of the seat of power, they were so much under confusion. They did not have the guts to make the recommendation

that the Assembly should be dissolved and we should go to the polls. But, Sir, Mr. Karunakaran not only resigned his Ministry, he also said, let the Assembly be dissolved, we are prepared to go to the polls and face the people and get a fresh mandate. Whatever be the mandate, let the people of Kerala decide who should rule the State. Is there anything wrong in it? Is it against the principles of democracy or is it against the Constitution of this country?

Sir, this time they are accusing that the Governor failed to probe the chances of an alternative Government. Why, Sir? Everybody knows what the respective strength is. Even according to them our strength was 70+1, the Speaker. Iam not claiming the Speaker as belonging to our party.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: It wis 70—1, 69

SHRI M. S. RAMACHANDRAN: They were accusing our party that we were living on the vote of the Speaker. With that vote we were living, assuming that argument, we were 70+1. What are they? At the time of the resignation, what are they? Or, even after that, what are they? How did they get that 70? Everybody knows that 70 is an equal number. Seventy on the other side is a minority. Seventy on that side is a majority. So, our 70 is a different figure and their 70 is a different figure. How did they get their 70? By pulling out the Speaker. If their Speaker continued in his office of Speakership, they were having only 69, and we were having 71. That was the arithmetic. Politicians for convenience sake may forget arithmetics but two plus two is always four. Our strength was, before one of our members took up the office of speakership, 71. We had the support of 71, including the Speaker. They had the support of only 70, and minus the Speaker their support was 69. To bring it equal to our number and create a situation in which the Government can continue or the proceedings of the Assembly can continue, only by the casting vote of the Speaker, they made is equal number, by withdrawing their man from the office of Speaker. And after doing that they called the Speaker's casting vote as raping. If they venture to call it as raping, I venture to ask them who created the climate for raping, who created the necessity for raping? By withdrawing the Speaker you have increased your number from 69 to 70, as equal to our number. By sending our man to the Speaker's chair, our number was reduced to 70. Sir, this arithmetic. I am only trying to give them by way of a reply.

Sir, the position is this whether anybody wants it or not; the moment Mr. Karunakaran and our party thought that we will be having a majority in the Assembly, we accepted the office. The moment, it was known to us that we could not enjoy the majority in the Assembly, we did not hesitate, we did not delay even by a minute, to tended our resignation and go out of power. Unlike Mr. Nayanar we did not leave the Governor to guess or to use her discretion as to what should be done. As a responsible party working under democratic conventions, Mr. Karunakaran exercised his discretion and made a specific recommendation to the Governor that the Assembly should be dissolved.

Mr. Vice-Chairman, last time, these friends were prepared to face the poll. When the Assembly was kept under suspended animation, they were questioning us: Come on; let us fact the poll. dissolve the Assembly; come to the polls. Now, we have dissolved the Assembly. We are coming to the polls. Why are they afraid of the people of Kerala? Come on, be prepared to face them; be prepared to face the polls. Let us see the result, whatever it is. We are prepared to accept the democratic verdict of the people of Kerala. Why are you shy of it? Come on if you are really interested to get another mandate of the people of Kerala, if you are really interested in democratically elected Government. You

should withdraw your Statutory Resolution and support the motion, and then request us to expedite the polls. That is the only civilised, decent and democratic way of dealing with it. But instead of doing this... (*Time bell rings*) Kindly be at least fifty per cent considerate to me as you have been to others.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I thought you are concluding.

SHRI M. S. RAMACHANDRAN: Just two minutes more. Sir my friend Mr. Shiva Chandra Jha compared the period of pre-Indira Governments and Smt. Indira Gandhi's period. He was saying that during the period of Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri, there were only 8 times President's rule that was imposed in one State or the other, and during the period under Indiraji, there were 31 times. Sir, I am not disputing the figures. I am only trying to remind my friend as to what the political scene of the country was then and what it is now During those days there were fewer political parties with clear ideals and clear programmes. What has happened of late is, after every election, anyone who does not get a berth in the Government, thinks it fit to start a political party. After the convention of each party, all those people who could not get elected in their own party, came out, held a different flag and started a new political party. So, when there are more and more political leaders, when there are more and more political parties without any difference in ideology, without any plan or without any programme, and when the political scene of the country has become so much polluted, so much multifaced, so much divided, the result is obvious. But this is not our creation; it is the creation of somebody else, and I do not want to say who created it. Therefore, it is not the Congress Ministers or the Congress Governments who go to each Assembly and arrange for cross voting and things like that. If the ruling party in the Assembly loses its majority and the Governor of that State in his or her wisdom makes a recommendation, it is the constitutional responsibility of the President of India and the Central Government to act on such a recommendation and then discharge their Constitutional responsibility. In that way, as I said in the beginning, the Governor of Kerala has submitted her report about the constitutional crisis there, about the resignation of the Karunakaran Ministry, and about the recommendation of the Karunakaran Ministry for dissolving the Kerala Assembly. Accordingly, she did her duty under the Constitution and the President and the Central Government have discharged their duties under the Constitution and, therefore, the Motion should be defeated. I would appeal to my hon. colleagues to support the Statutory Resolution and defeat the Motion moved by Shri Jha. Thank you, Sir.

3 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Shri Mathur. Mr. Mathur, you have seven minutes. (*Interruptions*) You must keep your word to the Business Advisory Committee. आपको सात मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन, ज्ञानी जी बड़े ज्ञानी हैं । उन्होंने बात सही कही कि इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है, ऐसेम्बली भंग हो गई है । यह प्रस्ताव पास भी हो गया तो भी वह दुबारा जिन्दा नहीं हो सकती । क्या बात आपने कहीं ? इसको मार डालो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे । मर गया तो मर गया, वह जिन्दा नहीं हो सकता । कत्ल करते हैं, कत्ल के बाद सीनाजोरी भी । सीनाजोरी अगर कोई सीखे तो सरदार जी से सीखें । एक तरफ कत्ल करते हैं और दूसरी तरफ आंखें दिखाते हैं । ऐसेम्बली टूट गई, यह बात सच है । चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं है ।

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

लेकिन मेरा श्रीमन्, ऐतराज यह है कि 356 धारा का उपयोग सतत अपने विशेष, हितसाधन के लिए किया जाता रहा है । मेरे मित्र श्री झा ने पंडित जवाहरलाल जी की तारीफ की । मुझे कोई ऐतराज नहीं । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पंडित जवाहरलाल जी के समय में ही इस धारा का उपयोग पहली बार 1952 में किया गया जब पंजाब में कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी श्री सच्चर और गोपीचन्द भार्गव का झगड़ा चला था । आपस का झगड़ा था लेकिन आपस के झगड़े को निपटाने के लिए इस धारा का उपयोग किया गया । ऐसेम्बली को सस्पेंड रखा गया और जब सच्चर और भार्गव का फैसला हो गया तब दुबारा मिनिस्ट्री बनाई गई । प्रारम्भ तो यहां से हुआ है । इसी तरह से एक बार नहीं दो बार नहीं, अनेक बार इसका दुरुपयोग किया गया है । मेरे साथी रामाचन्द्रन जी ने बड़ी बहादुरी से कहा कि कांग्रेस (आई०) तो लोकतंत्रवादी हैं, एक सदस्य ने पार्टी छोड़ दी और सरकार ने रिजाइन कर दिया । बहुत अच्छा है । लेकिन इसके पीछे एक खेल है । वह खेल यह है कि कब ऐसेम्बली भंग हो ताकि आगे केयर टेकर गवर्नमेंट हमारे हाथ में रहे । आपने एक दो बार नहीं, अनेक बार ऐसा किया है । आपने कहा कि जब कभी किसी मुख्य मंत्री ने कहा, हमने ऐसेम्बली भंग कर दी । करुणाकरन ने कहा, हमने भंग कर दी । मैं पूछना चाहता हूं कि सन् 1968 में क्या हुआ था ? यू० पी० में जब चौधरी चरणसिंह ने रिजाइन किया और सिफारिश की कि ऐसेम्बली डिजाल्व कर दी जाए, तो आपने डिजाल्व नहीं की थी । ऐसे ही सन् 1976 में जनता मोर्चे की सरकार गुजरात में थी, जनता मोर्चे की सरकार का इस्तीफा देते हुए बाबू भाई पटेल ने सिफारिश की थी कि ऐसेम्बली डिजाल्व कर दीजिए, आपने नहीं की । लेकिन इसके विपरीत वैस्ट बंगाल में अजय मुखर्जी की सरकार थी, उन्होंने नहीं कहा था लेकिन आपने ऐसेम्बली डिजाल्व कर दी । मतलब यह है कि जब जब कांग्रेस सरकार को यह दिखाई देता है कि हमारी पार्टी का फायदा है तो 356 धारा को मोम की नाक की तरह मरोड़ देते हैं । जब 1952 में आपस के पार्टी के झगड़े को सुलझाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो इस धारा का उपयोग किया गया । अगर इनको लगा कि दूसरी विरोधी सरकार आ जाएगी तो विधान सभा को भंग कर दिया गया । इस समय भी यही खेल था । अगर 70-70 की बराबरी थी तो स्पीकर के माध्यम से वोट देकर ऐसेम्बली बच सकती है, अगर 69-71 की है तो इसमें खास फर्क नहीं पड़ता । परन्तु आपने कहा कि इससे बहुत फर्क पड़ता है । ज्ञानी जी ने कहा कि गवर्नर की नियुक्ति जनता सरकार ने की थी, मैं मानता हूं । लेकिन कमाल यह है कि जिस चीज को दबाव डालकर आप नहीं करा सकते, उसका उपयोग आपने महिला से करा दिया । गवर्नर आप का हो, या हमारा नियुक्त किया गया हो, आप में कुछ ऐसी कला है कि आप उस से जो चाहें करा लेते हैं । दुर्भाग्य है केरल का । केरल की राजनीति कुछ अलग रही है । जिस दिन 1956 में केरल प्रदेश बना उस दिन से आज तक केरल में स्थायित्व नहीं आ सका और इस कुप्रारम्भ की जिम्मेदारी मैं कांग्रेस पर डालता हूं । मुझे याद है जब पहली कम्युनिस्ट मिनिस्ट्री बनी थी, उस के कुछ महीनों के अन्दर एक आंदोलन खड़ा किया गया । साम्यवादियों के साथ मेरा कोई प्रेम नहीं है । मैं तो ऐसे

बीच में खड़ा हूं कि एक तरफ नागनाथ साम्यवादियों का और दूसरी तरफ सांपनाथ कांग्रेस आई का । न ये अच्छे हैं, न वे अच्छे हैं । एक आज लोकतंत्र समाप्त कर रहा है दूसरा लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता । यदि वह कल गद्दी पर आ जाए तो वह उसे बिलकुल समाप्त ही कर देगा । मेरा रास्ता बिलकुल साफ है । मैं दोनों के विरोध में हूं । उस समय भी आज की प्रधान मंत्री जो कांग्रेस (आई०) की अध्यक्ष हैं । उस समय की कांग्रेस की प्रधान थीं । उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरु के आशीर्वाद से इस आंदोलन का साथ दिया । मन्नज पद्मनाभन उस समय जीवित थे । कहां को वह नायर सोसाइटी के नेता थे । उन के नेतृत्व में सारा केरल इक्ट्ठा हो गया था--- हिन्दू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, सारे खड़े हो गये थे और वह सरकार गिरी । किसने आरम्भ किया ? आज की श्रीमती गांधी ने वह आंदोलन तेज करवाया और केन्द्र में अपने पिता से कह कर सरकार को गिरा दिया । दूसरा हथकंडा देखने में आता है जब कम्युनिस्ट सरकार बनी पी एस पी की पीठ पर, आप उस में शामिल थे, सरकार खत्म हो गयी । आप ने पटट्म थानु पिल्लई को उठा कर पंजाब का गवर्नर बना दिया और सरकार गिरा दी । लेकिन वहां की राजनीति का कमाल एक और है । वहां तीन बातें उभर कर सामने आयीं जिन का सब खुले आम विरोध करते हैं लेकिन अन्दर से इसी का समर्थन करते हैं । नम्बर एक, सांप्रदायिकता केरल की राजनीति में घुसी हुई है । हर एक कहता है कि हम बड़े राष्ट्रवादी हैं, हमें सांप्रदायिकता के विरोधी हैं, लेकिन कोई पार्टी है जो वहां की राज्य सरकार में रही हो और उसने मुस्लिम लीग के साथ समझौता न किया हो ? कांग्रेस आई ने समझौता किया, पी. एस. पी. ने किया, सी पी आई ने समझौता किया । दूसरी है, अवसरवादिता । कोई पार्टी ऐसी है केरल में जो टूटी नहीं है ? कांग्रेस टूटी, कम्युनिस्ट पार्टी टूटी, मुस्लिम लीग टूटी, हर एक पार्टी टूटी । सांप्रदायिकता और अवसरवादिता यह वहां की राजनीति की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं । तीसरी बात है---वह ध्येय कांग्रेस आई का न हो, कम्युनिस्ट पार्टी का अवश्य है---हिंसा, मर्डर की राजनीति या तो लोकतंत्र चलेगा या हिंसा की राजनीति चलेगी । बंगाल में भी यही किया गया था । उस की अच्छाई बुराई में मैं नहीं जाना चाहता । जब तक यह तीन चीजें केरल की राजनीति में रहेंगी तब तक वहां की राजनीति स्थिर नहीं हो सकती । इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि वहां कोई भी गवर्नर बैठा हो, चाहे आज का गवर्नर हो या कोई और हो, वह पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ कर ऐसी स्थिति पैदा करे कि वहां स्थायित्व आ सके । मुझे दुख है यह कहते हुए कि वहां की गवर्नर महोदया ने न्याय नहीं किया । पहले तो उन्होंने दो महीने दे दिये सरकार बना कर हास ट्रेडिंग के लिये । क्यों दे दिये ? कहते हैं कि श्री नायनार ने असेम्बली डिजाल्व करने की सिफारिश नहीं की थी । मुझे विश्वास है कि जाते हुए यदि श्री नायनार ने कहा भी होता कि आप विधान सभा भंग कर दें तो भी विधान सभा भंग नहीं की जाती । गवर्नर कहती हैं "आज सुबह 11 बजे मुझे से मिले और उन्होंने मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र दे दिया । उन्होंने सूचित किया है कि उन की मंत्रिपरिषद की सिफारिश है कि राज्य विधान सभा को भंग कर दिया जाये ।" आगे कहती हैं "मैं स्वयं इस बात से संतुष्ट हूं

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

कि किसी व्यावहारिक, स्थायी या स्थिर सरकार बनने की संभावना नहीं है ।" इस में कितनी देर लगी ? मुख्य मंत्री 11 बजे मिले और 12, साढ़े बारह बजे नोटिस निकाल दिया । मतलब क्या है यह कहने का कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि वहां कोई स्थायी सरकार नहीं बन सकती ? यह बिल्कुल गलत है । उन का मन पहले से बना हुआ था । एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 24 घंटे का समय भी लिया होता और विरोधी दलों के नेताओं को बुला कर बात चीत की होती या जो डाउटफुल एम एल ऐज थे उन को बुला कर बात की होती तो पता लग जाता । लेकिन साफ है कि पहले से उन का मन बना हुआ था । क्यों बना हुआ था ? क्योंकि खेल इस बात का था कि कांग्रेस (आई.) चाहती थी कि विधान सभा भंग तो हो लेकिन ऐसा हो कि उस के बाद काम चलाऊ सरकार की बागडोर उनके हाथ में रहे । यह सारा खेल है, सीधा सीधा खेल है जो इन्होंने गवर्नर के माध्यम से खेला । तो श्रीमन, आप ने कहा है कि विधान सभा भंग होने के बाद अब दुबारा केरल में सरकार नहीं बन सकती । मैं मानता हूं कि नहीं बन सकती । मैं अपील करना चाहता हूं कांग्रेस आई से, सी पी आई से और सी पी एम से, उन के नेताओं से और दूसरे विरोधी दल के नेताओं से कि राजनीति का यह रास्ता छोड़ दें । कहावत है कि इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं । कोई ईमानदार नहीं है । कोई भी बचा हुआ नहीं है सांप्रदायिकता से । कोई भी राजनीतिक भ्रष्टाचार से बचा हुआ नहीं है । यह बातें सब जानते हैं । इस लिये मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं आप लोग हिंसा को छोड़ दीजिए, आप लोग सांप्रदायिकता को छोड़ दीजिए । अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक है तो उस के अनुसार आचरण करिये । लेकिन इन्दिरा गांधी जी घोर साम्प्रदायिक मुस्लिम लीग के साथ केरल में सरकार बना कर बैठीं । कहती थीं कि यह मुस्लिम लीग पहले की मुस्लिम लीग नहीं है । लेकिन मुस्लिम लीग के नेता ने जवाब में कहा कि हम वही हैं जो पहले थे आप का मुस्लिम लीग से समझौता हो सकता है और उस के बाद भी आप कहते हैं कि आप सांप्रदायिक नहीं हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप राजनीतिक शुद्धता लाइये । आप केरल में शुद्ध चुनाव कराइये और जल्दी कराइये इस लिये कि वहां सरकार बने जन प्रतिनिधियों की, लेकिन उस में किसी अवसरवादी को घुसने न दें । आप उन को सीधे सीधे कहें कि आप अलग रहें । जब तक यह अवसरवादी केरल में रहेंगे, आप के हाथ में सरकार रहे या किसी दूसरे के हाथ में रहे, तब तक केरल में शान्ति नहीं होगी और हिंसा भड़कती रहेगी । एक ही रास्ता है केरल के लिये । ऐसा रास्ता जो शुद्ध देश भक्ति का है । प्रतिनिधि अवसरवादी न हों और वे सांप्रदायिकता के नाम पर अपनी रोटियां न सेकें । इस लिये मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं कि ऐसा रास्ता अपनायें तो देश का और केरल प्रदेश का भला होगा । ज्ञानी जी ने ठीक ही कहा है कि असेम्बली तो दुबारा जीवित नहीं हो सकती, अगर कोई कोर्ट भी फैसला दे दे तो भी जीवित नहीं हो सकती । लेकिन आप ने कत्ल तो किया ही है । हम एतराज तो करेंगे ही । आप कत्ल करें और साफ बच कर चले जायें और हम कुछ न बोलें, यह कैसे हो सकता है ।

श्री पी० एन० सुकुल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो राष्ट्रपति की

उद्घोषणा हुई है केरल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय एक बहुत विचित्र स्थिति आज हम अपने देश में देख रहे हैं जितनी विरोधी पार्टियां हैं विशेष रूप से उनके बारे में । वही काम तीन महीने पहले या चार महीने पहले अगर हो जाता तो ठीक था । अगर चार महीने बाद वही काम हो रहा है तो गलत है । डबल स्टैंडर्ड का चार्ज हमारे ऊपर लगाया जाता है और मेरा अपना विश्वास है कि डबल स्टैंडर्ड हमारे विरोधी दल के लोग ही अपनाते रहे हैं । आज अगर वहां के चीफ मिनिस्टर की रेकमेंडेशन न मानी जाये तो हमारे विरोधी दल के लोग प्रसन्न होंगे । आज वहां का गवर्नर अगर स्थिति का सही आकलन कर के उन के मन मुताबिक कोई अपनी राय देता है तो वह मानेंगे, लेकिन अगर उन के हित के खिलाफ वह कोई रिपोर्ट देता है तो वह उसे नहीं मानेंगे, न वह चाहते हैं कि गवर्नर वहां अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करें, न वह चाहते हैं कि मुख्य मंत्री अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करे । अगर वह वही करे कि जो विरोधी दल चाहता है तो वह तो लोकतंत्र की स्थिति नहीं है । हमारे झा जी कहते है कि जनतंत्र का चीरहरण हो रहा है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस को आप जनतंत्र का चीरहरण कैसे कहेंगे । जिस समय नयनार मिनिस्ट्री गिरी उस समय अगर यही काम कर लिया जाता तो जनतंत्र का चीरहरण नहीं होता, लेकिन आज अगर करुणाकरण जी की मिनिस्ट्री गिरी है और जिस तरह की रेकमेंडेशन आयी, उस के बाद गवर्नर ने वहां की स्थिति का जायजा लिया और उस ने पाया कि एक स्थायी सरकार वहां नहीं बन सकती है । इस लिये उस ने रेकमेंड किया राष्ट्रपति जी को कि यहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये क्योंकि यहां स्थायी सरकार नहीं बन सकती है । उस के बाद ही वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और हमारे विरोधी दल के लोग व्यर्थ ही हल्ला मचा रहे हैं । अभी आप कह रहे थे चार महीने पहले चुनाव कराने की बात । अब चुनाव हो रहा है, पर आप नहीं चाहते हैं । ऐसा मालूम होता है कि पहले चुनाव चाहते थे, अब नहीं चाहते हैं । हमें ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों ने अपनी कमजोरी को महसूस कर लिया है कि बहुत संभव है कि अब अगर चुनाव होते हैं तो उस तादाद में, उस संख्या में, जिसमें ये अब हैं, नहीं आ पाएं । आप जानते हैं कि वहां पर वामपंथी मोर्चा था । उसकी सरकार का चलन और उसके कार्यों को आप देखें तो पता चलेगा कि वह पर स्प्रिड स्कैंडल हुआ और दूसरे भी इसी प्रकार के कार्य हुए । चाहे उनकी इंडस्ट्रियल पालिसी रही हो, चाहे प्लान्ड डेवलपमेंट का कार्य रहा हो, इन्होंने उस सारे पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जो इन कामों के लिए दिया गया था । ये कहते थे कि अपने प्रदेश में प्लान्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं कर पाये । जहां तक हमारी सरकार की बात है, पिछले साल भी हमने उसके लिए 275 करोड़ रुपये रखे थे और इस बार भी यह राशि रखी है । हम सरकारों में कोई फर्क नहीं करते हैं । चाहे हमारी सरकार हो या किसी और की सरकार हो । जरूरत के मुताबिक चीजों का आंकलन किया जाता है और आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्था की जाती है । लेकिन वहां की सरकार की तो यह स्थिति थी कि जब वामपंथी मोर्चे की सरकार थी तो वह खुद अपने कर्मचारियों से हड़ताल करवाती थी । आज हमारे देश में पश्चिमी बंगाल, केरल और त्रिपुरा में, तीन प्रदेशों में ऐसी सरकार हैं जो खुद अपने कर्मचारियों से हड़ताल करवाते हैं । अब सोचने की बात यह है कि इस प्रकार से अगर सरकार के कहने

[श्री पी० एन० सुकुल]

से कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो यह रिवोल्यूशन है या काउंटर रिवोल्यूशन है ?

श्री दीपेन घोष (पश्चिमी बंगाल) : आपके उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है. . . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): No, please. Your turn will come. Kindly listen now.

श्री पी० एन० सुकुल : हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद अपने कर्मचारियों से हड़ताल करने के लिए नहीं कहा है। लेकिन आपकी पश्चिमी बंगाल की सरकार और त्रिपुरा की सरकार तो अपने कर्मचारियों से हड़ताल करने के लिए कहती है. . . **(व्यवधान)** हमारी सरकार अगर अपने कर्मचारियों से पश्चिमी बंगाल में हड़ताल करने के लिए कहे तो वहां पर हड़ताल करेंगे। इसी प्रकार से हमारी सरकार केरल में अपने कर्मचारियों से हड़ताल करने के लिए कहे तो कर्मचारी वहां पर हड़ताल करेंगे। लेकिन भारत सरकार अपने कर्मचारियों से हड़ताल करने के लिए कभी नहीं कहेगी। हमारा शासन एक जिम्मेदार शासन है। देश भर में उसे शासन चलाना है और देश भर में संविधान के अनुसार कार्य करना है. . . **(व्यवधान)** ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please let us have the debate in a....

श्री पी० एन० सुकुल : हमारी सरकार अपने कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए नहीं कह सकती है। हमारे घोष साहब. . . **(व्यवधान)** कोई भी इम्प्लायर अपने इम्प्लाईज से स्ट्राइक करने के लिए कहे तो क्या वह रियल स्ट्राइक है ?

Is it a real strike? This is what I am asking.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I think both of you belong...

SHRI P. N. SUKUL: I seek your protection, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): How can I protect you from your own ex-General Secretary?

श्री पी० एन० सुकुल : : केरल में जो पार्टियां रही हैं और जो तथाकथित वामपंथी मोर्चा था उसमें मुस्लिम लीग भी थी। अभी हमारे साथ श्री माथुर ने कहा कि वह एक कम्युनल पार्टी है। वामपंथी मोर्चे में जो तथाकथित वामपंथी मोर्चा था, उसमें समाजवादी और क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक पार्टियां भी थीं। इसीलिए मैं उसको तथाकथित वामपंथी मोर्चा कहता हूं। वह वामपंथी मोर्चा केरल में सफल नहीं हुआ।

SHRI B. V. ABDULLA KOYA: Mr. Sukul...

SHRIMATI USHA MALHOTRA (Himachal Pradesh): No, this is not the way.

SHRI B. V. ABDULLA KOYA: I am sorry but, Mr. Sukul, the Muslim League had some electoral understanding with the BJP during the last elections... *(Interruptions)*... I am supporting you by saying that the Muslim League had some electoral understanding last time with the BJP in Kerala.

श्री पी० एन० सुकुल : मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके हित में अगर कोई बात होती है तो वह बिलकुल सही है, लेकिन हमारी पार्टी अगर केरल प्रदेश में रहने वालों के हित में या पूरे देश के निवासियों के हित में वही काम करती है तो आप उसको गलत बताते हैं। यह डबल स्टेन्डर्ड, डुयल एप्रोच कैसे चलेगी ? दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा केरल प्रदेश जहां सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोग रहते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा लिट्रेसी है, जहां पर सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, वहां हम देखते हैं कि 31 बार राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा चुका है। यह हमारे

लिए सोचने की बात है । जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं वे वहां पर होर्स ट्रेडिंग को गुंजाइश देखते हैं । कैसी विचित्र स्थिति है कि अगर अपने वामपंथी मोर्चे से सबक लेकर कोई आदमी इधर आता है तो वह डिफेक्शन हो जाता है; लेकिन अगर आप हमारे आदमी को ले लेते हैं तो वह डिफेक्शन नहीं होता है । वह चलना चाहिए । गवर्नर जिसका अपना स्वतंत्र मत रहता है और गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है गवर्नर की जो अपनी बुद्धि है, विवेक है, उसके ऊपर यहां शंकाये की जा रही है । हमारे माथुर साहब कह रहे थे कि आपकी सरकार ने गवर्नर से यह काम करवाया । माथुर साहब, आप जाइये और गवर्नर से खुद मिलिये और पूछिये कि जो रेकमेंडेशंस उन्होंने भेजी हैं, क्या वे हमारी सरकार के कहने पर भेजी हैं या अपने विवेक के कहने पर भेजी हैं और अगर अपने विवेक का प्रयोग करके उन्होंने ये रेकमेंडेशंस भेजी हैं तो इस प्रकार के अनुत्तर दायित्वपूर्ण चार्ज आपको लगाना नहीं चाहिए । ऐसा करके न आप अपनी पार्टी की छवि को उज्ज्वल करते हैं और न भारतवर्ष में लोकतंत्र की नींव को आप मजबूत करते हैं । हमारी प्रधानमंत्री के ऊपर आपने यह चार्ज लगाया कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने ऐसा करवा और तब करुणाकरण की सरकार गिरी । एक बार भी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि तुम अपनी सरकार को रोको और न यह कहा कि तुम गिरा दो । हमारी प्रधानमंत्री के जो रवैया रहा है शुरू से 1980 में आने के बाद, अगर वह चाहती तो आपके खिलाफ स्पैशल कोर्ट का निर्माण हो सकता था । प्रधानमंत्री हमारी विंडेक्टिव नहीं । उन्होंने कहा कि जो काम ये लोग कर गये हैं, जनता पार्टी और चरणसिंह कर गये हैं वह इस तरह का विंडेक्टिव नहीं दिखायेंगी, केवल परेशान करने के लिये किसी को परेशान नहीं करेंगी । हम स्पेशल कोर्ट बना करके उनका चीर-हरण नहीं करेंगे । हमारी प्रधानमंत्री को आप बात मत कीजिये । रही राजनीति की बात । राजनीतिक पार्टी आप भी है और राजनीतिक पार्टी हम भी है । यह सियासत की बात है कि अगर आप अपना हित देख सकते हो तो आपको क्या ऐतराज है जब कि दूसरी राजनैतिक पार्टियां अपना हित देखती हैं । हम तो नहीं कहते, जब वहां पर नयनार जी की सरकार बनी, हमने नहीं उनको गालियां दी, हमने कोई भलाबुरा नहीं कहा ? क्या हमने उससे उनके प्लान में कटौती कर दी और असिस्टेंस जो दे रहे थे क्या वह नहीं दे रहे हैं ? हमने हर एक प्रदेश को, हर एक प्रांत को एक तरह से देखा । लेकिन आप अपनी सरकार को चला नहीं पाये । सरकार जब नहीं चली तो आज कह रहे हो कि नहीं यह गलत हुआ । मैं समझता हूं कि यह जनतंत्र की मांग थी कि यहां पर चुनाव हों । एक बार तो मौका दिया जा सकता है । जब नयनार जी की सरकार गिरी जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि यह रेकमेन्डेशन नयनार जी ने नहीं की कि हाउस की डिजाल्व किया जाये, असेम्बली को डिजाल्व किया जाये, यह उनकी रेकमेन्डेशन नहीं थी । परन्तु गवर्नर को पूरी स्वतंत्रता थी कि वह अपने विवेक से देखता कि वहां पर अल्टरनेटिव गवर्नमैन्ट बन सकती है या नहीं बन सकती है। टु एक्सप्लोर दि पासिबिलिटी हमारे गवर्नर ने समझा कि यहां पर सरकार बन सकती है। दुबारा जब करुणाकरण की सरकार गिरी तब उन्होंने यह रेकमेन्डेशन स्वयं की कि हाउस डिजाल्व होना चाहिए और गवर्नर ने भी उनसे एग्री किया । एक आदमी इधर आ गया, दुबारा फिर उधर भी जा सकता है तो ऐसी स्थिति में आदमियों का आना जाना जबकि डिफेरेन्स अन्तर, बहुत ज्यादा नहीं है, तो यह यहां की जनता के हक में है यहां के लोकतंत्र के हक में हैं कि वहां जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायें और इसलिये राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई और वहां पर राष्ट्रपति

[श्री प० एन० सुकुल]

शासन लागू किया गया। महोदय, आज देश में कितना प्राविंशियलिज्म चल रहा है कितना रीजनलिज्म चल रहा है, कितना कम्युनलिज्म है, सेकटेरियनिज्म है तो तो ये कितने मत मतांतर है, जो बाद हैं, संकुचित दृष्टिकोण जो सामने आते हैं तो इस दृष्टिकोण से चल कर हम अपने देश का भला नहीं कर सकते। मैं तो महोदय, पिछले 33-34 सालों से जो यहां जनतंत्र है भारतवर्ष का और हमारी विरोधी पार्टियों का जो रवैया है इन सब को देखने के बाद व्यक्तिगत रूप से मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि राष्ट्रपति शासन जो वहा लागू हुआ, उसकी बात नही हमारे देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू होनी चाहिए, तब हम चल पायेंगे। ...(**व्यवधान**)... बिल्कुल। बिना राष्ट्रपति प्रणाली के आये हुए मै आपको बता दूं कि आप इसी तरह से हल्ला मचाते रहेंगे हाहा-हू हू करते रहेंगे, तबला और ढोलक बजाते रहेंगे। यहां शासन तभी चलेगा जब राष्ट्रपति प्रणाली यहां पर लागू होगी। कोई कारण नहीं अगर वह अमेरिका में लागू हो सकता है, फ्रांस में लागू हो सकता है तो हिन्दुस्तान में क्यों नहीं लागू होना चाहिए। मैं... (**व्यवधान**).. तब यह मौका नही मिलेगा ... (**व्यवधान**) .. इसलिये महोदय, मैं इन शब्दों के साथ हमारे गृह मंत्री द्वारा लाया गया जो प्रस्ताव है, राष्ट्रपति शासन का उसका मैं समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Joseph. I think you know that your time is only seven minutes.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: I have a submission, Sir. Mr. Sukul has pleaded for the Presidential form of Government in this country. He has fallen short of the oath he has taken in this House as a Member. Therefore, I question the very propriety. Therefore, this matter should be off the record.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I do not think so. (*Interruptions*)

SHRI SADASHIV BAGAITKAR (Maharashtra): Keep it on record.

SHRI ARABINDA GHOSH (West Bengal): He will be dismissed from the Membership of Rajya Sabha.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Why should you bother about it? Please, Mr. Joseph.

*SHRI O. J. JOSEPH (Kerala): Mr. Vice-Chairman Sir, I rise to oppose the proclamation issued by the President in relation to the State of Kerala.

Last time when we met here we had protested against the action of the Kerala Governor for making the Members of the Kerala Assembly wait in the 'Trishanku' or for keeping them in suspense to see whether they could be tamed as desired. We had pleaded that this approach was wrong and elections should be held as early as possible. Then what was said from the Government side? They said that simply because some persons had erred it is not proper to punish all the Members and therefore, it is not proper to dissolve the Assembly. Now the situation has changed. There is no change in our stand. It is the ruling front which has changed their stand. They had started this process of horse-trading. It was the tradition of the Congress Party—right from the beginning to cause splits, defections etc. not only in other parties but also in their own party itself. It

*English translation of the original speech delivered in Malayalam.

was with the same objective they split the Janata Party into two. Antony walked out with his group earlier. They have also been split into two. Are not these Congress Governments constituted of all kinds of elements under Gundus and Lals? It is not a new phenomenon. When we demanded dissolution earlier they did not agree. Now they say that it was the Governor's decision. They claim that she is a great lady. But she is either a tool in the hands of this Government or she is a* * *. Why could not she dissolve the Assembly earlier? It is on the specious plea that Mr. Nayanar did not tender any advice to that effect.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: He has used the word** for the Governor. I think it should be expunged. I do not know whether the translation is correct or not.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I will look into it.

SHRI O J. JOSEPH: Sir, I was trying to narrate why she could not dissolve the Assembly earlier.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): If that word has been used, that should be expunged. Please go on.

*SHRI O. J. JOSEPH: Sir, then she could not decide on the question of dissolution. Now within an hour she could take the decision. Therefore, it is obvious she has either consulted the Centre before the dissolution or her conduct has not been fair in this regard.

It was on 15th Mr. Lonappan Nambadan had withdrawn his support. Mr. Karunakaran submitted his resignation on 17th. There was enough time in between for giving serious thought to the matter, as we understand it. Similarly when Mr. Nayanar also submitted his resignation she had all the time at her disposal to consider the matter. Therefore, there is no question of her having taken a decision independently when the Antony group walked out why the Government did not resign? If 22 members go out of 95, still the Government enjoyed majority? They did not resign because they owed some sense of responsibility not only to the entire people of the State but also to the other parties in the left democratic front. That is why they did not resign at that time. Therefore, we are of the view that Chief Ministers who do not enjoy majority in the Assembly should not tender any advice to the Governor in regard to matters like dissolution. We did not tender any such advice.

Now the Governor who is supposed to go into all these matters could have asked the Congress Party to form the Government after the Nayanar Ministry's resignation if they had a majority. Then why she kept the matter in suspense for two months. Now it is obvious that the Congress led front had no majority at that time. Even after prolonging the matter for two months they could not secure an absolute majority. The Janata Party had already declared that they would decide only after Mr. Karunakaran has formed the Ministry and come to face the Assembly. The Janata Party leaders said that he had not assured any support. That is why I said that the Governor who allowed the Congress to form a Government with the support of 67 Members is either a rubber stamp of the Centre or she does not deserve to hold that office.

Some Hon'ble Members said here that we are criticising the Government because she has dissolved the Assembly. We have only one objection. When we said that we enjoyed the support of 71 Members, at least as a matter of courtesy, she should have enquired from us whether we were in a position to form an alternative

---

***Expunged as ordered by the Chair.

*English translation of the original speech delivered in Malayalam.

[Shri O. J. Joseph]

Government. Whether it was possible to form a government or not is a different matter. Perhaps it was not possible or we would have recommended for dissolution. But why she did not show this elementary courtesy to us? That is the objection. Therefore, the whole episode is beset with double standards. The Home Minister said here that the Governor is very competent and all that. But what she has done after the imposition of President's rule? She is indulging in malpractices and favouritism by appointing a P.S.C. Member which even Mr. Karunakaran did not dare to do. Is it proper for a Governor to do that.

Therefore, the question is not one of winning or losing the elections; that we can see when the time comes—we had demanded at that time for dissolution and early elections. But they did not do that. Now they have dissolved the Assembly. They say that our strength and popularity have eroded now, and that is why we are criticising the dissolution. I do not know whether they claim that Shri Karunakaran has swelled his ranks or we have lost our grounds. Nothing like that has happened. Therefore, the elections could have been held earlier. Then the State Assembly could have elected the States representative to the Rajya Sabha in the current biennial elections. Who are to be blamed for this situation.

Next the question of Assam is coming up. Inspite of having a majority they could not form a Government there. Why are they trying to create splits in other parties? We still remember Mr. Makwana, he is not present here, and Mr. Stephen frequently coming to Kerala in their efforts for creating grounds for the dismissal of the Nayanar Ministry. They promised 22 seats to the Mani group. The big toddy shop contractors were mobilised to spend money and to do all sorts of immoral and unprincipled practices to remain in power. Still they failed to remain in power. While going out after submitting the resignation Mr. Karunakaran claimed that he had been offered support by an opposition member. Thus he tried to strick to power till the last moment.

Sir, in the first general elections Shri Pattom Thana Pillai's Government was voted to power with almost hundred per cent majority in the then Travancore-Cochin State. They could not rule for six months. Thereafter, the A. J. John Government could not last for six months. Shri C. Kesavan's Government also met the same fate. Afterwards Shri Panampilli Govinda Menon who later became a Central Minister, while tendering the resignation of his Ministry in the State said with tears in his eyes that it was his own partymen who brought about his downfall. Leg-pulling has always been the tradition of the Congress Party. That is why there are so many shades of Congress Parties in Kerala such as Kerala Congress M, A.B.C. etc. etc. now. Therefore, they must understand that these sorts of things are taking place only because of their anti-people and anti-democratic policies and practices. Nobody else need be blamed for this. As a result of this they have created enormous difficulties for the people. Therefore, I have to ask just two questions of them.

When are you going to hold the elections? We are still of the view that the elections should be held as early as possible. Our apprehension still is whether it would be indefinately postponed. Secondly much was said here about horse-trading, defections etc. But I would like to ask whether they are prepared to bring forward a legislation for putting a stop to this defection. Thank you.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है तो इससे वह यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में जहां-कहीं गैर कांग्रेसी सरकार है वहां ऐसा

ही प्रस्ताव लाया जाए, ऐसी मंशा इससे जाहिर होती है।

सवाल यह है कि हिन्दुस्तान के अंदर, कांग्रेस सरकार, जम्हूरियत को, प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती है या उसको ताकत देना चाहती है। यह सवाल है। जो कार्यवाही सरकार कर रही है जो जरिया कांग्रेस सरकार की तरफ से हो रहा है इससे पता चलता है कि यह जम्हूरियत का गला घोटना चाहती है, प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है, जनतंत्र को खत्म करना चाहती है। यह अजीब बात है, अफसोस की बात है कि जब केरल में नयनार की सरकार गिर गई, बहुमत नहीं मिला, उस वक्त तुरंत यह चाहिए था कि असेम्बली को भंग करते और चुनाव का इलान करते। उस वक्त यह तो नहीं किया गया। उन्होंने यह चाहा कि किसी सूरत में बहुमत हो या सच हो, करुणाकरन को मौका दिया जाए और ऐसे हालात पैदा किये जाएं जिससे कि जो दूसरे दलों के मेम्बरान है, उनको किसी तरीके से उनकी तरफ लाया जाय, यह मौका दिया गया। यह तो गैर-जम्हूरी तरीका है यह प्रजातंत्र के और जनतंत्र के विरुद्ध है। ऐसी कार्यवाही जो केन्द्र की तरफ से की जाती रही है वह प्रजातंत्र के खिलाफ एक साजिश है।

तो करुणाकरन को मौका दिया गया और जब वह इतना मौका देने के बाद भी उनके पास कोई मेजोरिटी नहीं थी जिससे कि उनको कहा जाए कि वे सरकार बनायें सिर्फ एक आदमी की मेजोरिटी से उनको सरकार बनाने का मौका दिया गया। उसका नतीजा उसी वक्त सभी ने कहा था कि यह सरकार दो दिन भी नहीं टिक सकेगी। उसका क्या नतीजा हुआ वह सरकार गिर गई। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब करुणाकरन को मौका दिया गया तो वह नयनार या दूसरी अपोजीशन पार्टी के जो लोग हैं; उनको भी मौका दिया जाना चाहिए था। इसके बरखलाफ राज्यपाल ने राष्ट्रपति के रूल का एलान किया है। यह जम्हूरियत के खिलाफ है। यही तरीका दूसरे राज्यों में भी जहां कांग्रेसी सरकार नहीं है, अख्तियार करने की कोशिश की गई है।

आपने असम में यही किया और वेस्ट बंगाल में यही करने की कोशिश की और त्रिपुरा में यही करने की कोशिश की, तमिलनाडु में यही करने की कोशिश की, लेकिन आपके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपने असम में राष्ट्रपति शासन कर दिया। तो इससे जाहिर होता है कि जहां आपकी सरकार नहीं है आप चलने नहीं देंगे आम लोगों की मर्जी के खिलाफ गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने का काम आप करते है और आपने किया है।

तो इस रवैये को सरकार को बदलना चाहिए क्योंकि इससे जम्हूरियत को ताकत नहीं पहुंचती है, जम्हूरियत नष्ट हो जाती है। तो मैं गृह मंत्री जी से यह चाहूंगा कि क्या वह इस जनतंत्र विरोधी तरीके को लागू करने से बाज आएंगे और जनतंत्र विरोधी यह नया रास्ता आपने जो अख्तियार करने का फैसला किया है तो फिर हिन्दुस्तान का भविष्य, हिन्दुस्तान का मुस्तकबिल अन्धकार की ओर होगा और इसका बयान नहीं किया जा सकता कि इसका भविष्य क्या होगा। सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में और जनता की इच्छा का आदर करना चाहिए। स्टेट आन्ध्र प्रदेश में अब तक चार साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदले गए। अंजेय्या जी यहां बैठते थे हमारे साथ उन को यहां से उठा कर ले गए और लोगों की मर्जी के खिलाफ उन को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और जब बना दिया गया उसके बाद उनको

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

हटा भी दिया गया। तो लोग कह रहे हैं क्या ऐसी ही परिस्थिति देश में चलती रहेगी ? हर राज्य में, पूरे देश के अंदर, कुछ समस्यायें हैं जनता की। बेरोजगारी की समस्या है, लोगों का पानी पहुंचाने की समस्या है, पीने का पानी पहुंचाने की समस्या है, उनकी जिंदगी की जरूरी चीजों को पहुंचाने की समस्याएं है। उनके हल करने की बजाय कभी इस सरकार को गिराओ दूसरी सरकार को लाओ इस पार्टी की सरकार को गिराओ उस पार्टी वाले को लाओ। अगर ऐसे कामों में केन्द्रीय सरकार लगी रहेगी तो हिन्दुस्तान की जो गरीबी है, हिन्दुस्तान की जो समस्या है, हर राज्य में जो जनता की समस्याएं है, उनको हल नही कर सकेंगे ।

केरल में आज करीब 2 लाख पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, उनकी समस्याओं को हल करना है और वहा छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज है जैसे कोयर इंडस्ट्री है, कोकोनट इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्रीज है, जिनको बहुत ही नुक्सान पहुंचा है। तो उन समस्याओं को हल करने का सवाल है और आपने एक पालिसी अख्तियार की है कि ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने की बजाय जैसे कायर इंडस्ट्री है, जिनकी चीजें यहीं तैयार हो सकती है पैदा हो सकती हैं, उनको बाहर से इम्पोर्ट करने की पालिसी अख्तियार किया है। इसलिए सरकार को अपने रवैये को बदलना है और साथ-साथ यह जो मौजूदा पालिसी है, जैसे केरल में और असम में अख्तियार की जा रही है इसको बंद किया जाए वरना आप अपने हाथ से ही इस जम्हूरियत का गला घोट देंगे

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Home Minister, at the outset, rightly pointed out that the Motion moved by the Opposition would, if voted, would create a situation in which there would be nothing to act upon.

(The Vice-Chairman (Dr. (Shrimati) Najma Heptulla in the Chair).? But the Home Minister knows very well that the Motion is moved only to registered the strong protest of the Opposition against the manner in which the entire parliamentary process has been subverted in Kerala during this entire period since the month of October 1981 to the 17th March 1982, when the Assembly was dissolved and subsequently the Presidential Proclamation was issued. The Governor, in her report, I mean, in her message dated the 17th March, 1982, made a very poignant remark: "Under the circumstances,", she says, "I am personally satisfied that there is no possibility of forming an alternative viable and stable Ministry." But, when earlier in the month of December,—28th December, to be precise—she recommended the revocation of the Proclamation of the President, did she do that after being convinced that there was a possibility of forming a viable and stable Ministry? I fully agree with the Home Minister that the office of Governor or any incumbent of the office of Governor should be spared any disparaging language. But what about the disparaging conduct of the incombent of the office of Governor? If the high office is denigrated by the occupant of that high office itself, if the incumbent of that office or anyone acts in a manner which is against the spirit of the Constitution as we see it, and recommends a party to form the Ministry which cannot continue for more than 2½ months, can it be called a viable or stable Ministry? How, 2½ months back, the Governor could come to the conclusion that there was a prospect of forming a stable and viable Ministry, a Ministry based on defections only? One lone defector was prized with one Cabinet post. That is the way in which the Ministry, remshackle Ministry, came

to be formed on the 28th of December, 1981. On the report of this particular Governor, who post-haste dissolved the Assembly, without giving the Assembly at least a chance to send their representatives to the Council of States, this was done in conjunction with the ruling party at the Centre. She did not concern herself with the question of viability or stability. On the eve of the Rajya Sabha elections, when the edge was on the side of the Opposition with reference to the Centre, this post-haste dissolution of the Assembly was done by this very Governor, who believed that there was no possibility of a viable and stable Ministry. The double standard resorted to by the Governor in Kerala exposes her to unsavoury remarks on very reasonable points and proper constitutional provisions. Our plea is that the treasury benches denigrate the constitutional process in such an inconsistent manner that really opens up the way to the dictatorship, apprehensions regarding which have been expressed in this country, particularly from the side of the Opposition who are the watch-dog of the Constitution. The constitutional process has repeatedly been denigrated. In Assam, where the ruling party was involved, the Governor did not think about the question of viability or stability, while in Kerala the Governor post-haste dissolved the Assembly, not giving it a chance even to send their representatives to the Rajya Sabha. This is a state of affairs which deserves all-round condemnation. An assurance must be forthcoming from the ruling party that if they want us to believe their protestation that they are belivers in the parliamentary system of democracy they would stop such practices.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): Mr. Abdulla Koya. You have seven minutes.

SHRI B. V. ABDULLA KOYA: Madam Vice-Chairman, I support the Proclamation issued by the President and also the Resolution moved by Giani Zail Singh.

Madam, it is due to the mistakes and blunders of the so-called United Left Front under the leadership and control of Marxist Party in Kerala that brought about such a situation in our State. Even though the Kerala electorate had given them a massive mandate in 1980 by returning their 102 MLAs out of 140 Members in the Assembly, they conveniently forgot that their majority did not reflect the actual support they got from the electorate, having got only 51 per cent votes against 49 per cent votes polled against them. The opposition parties, including my party, the Muslim League, had declared then that they would behave as the genuine responsible opposition supporting all the good measures of the Government and criticising and opposing only such acts of the Government which, according to them, may affect the State and the people, especially the backward classes.

But what happened? That Government failed miserably in every respect. People's expectations were brought down to the ground level. The number of Ministers jumped up to 17 instead of 14, for such a tiny State having 140 M.L.As. The number of highly-paid officers and departmental heads was increased. Even the number of Public Service Commission Members was increased to satisfy all the Constituent parties of the United Front. The number of corporations was increased. Pension to the agricultural labourers was a laudable measure, but it was misused by giving it only to a few selected people of their choice having their party tickets. Restrictions were brought in to curb the growth of Arabic studies in the State, culminating in spontaneous agitations and resulting in shootings and killings of young men.

[Shri B. V. Abdulla Koya]

The so-called Head Load labourers, under the patronage of their labour unions were let loose to create anarchy and lawlessness. Police people of the lower ranks were encouraged to organise themselves at the expense of discipline and sense of duty, thereby creating an atmosphere of lawlessness and political anarchy throughout the State. Prosecutions were launched only against their political opponents. I hope my friend, Mr. Mathur, also will agree with me so far.

No enquiry was ordered against charges of corruption by even some of the Ministers. The State Exchequer became empty by means of reckless expenditure forcing the Reserve Bank to stop overdrafts. The result was that nobody in the State felt secure. The State coffers have now to begin with deficit of 84 crores. They utterly failed to get the sympathies and help from the Central Government for the State Plan.

When they were about to lose the support of their two allied parties, they could have asked for the dissolution of the Assembly. But they failed to do so, because they were hoping to get the support of some other parties. When an alternate Ministry was formed, they made a hue and cry for getting that Ministry dismissed because that coalition was having only the support of 71 M.L.As. But when one member of this coalition broke away without actually joining them, they wanted the Governor to call them for the Ministry-making. That Ministry would have to survive with a doubtful casting vote of the Speaker again. Even that was doubtful.

Before I conclude, I request the Central Government to have some sympathy and toleration towards the aspirations of Kerala. The import of rubber, coconut, oil and pepper are against the interests of the struggling farmers of Kerala. This is the main reason for the Kerala people seeking a change in the Government so that they may get better treatment from all concerned.

Measures like building, expanding and maintaining national highways, railways, all-weather ports, etc. are much below our expectations and rightful demands. Kerala has thus become a problem State not only to Keralites but to India as well. I would suggest a thorough inquiry into the malpractices of the out-gone Ministers of any time before. It is because there were some Ministers who had not done well and those enquiries may bring out the truth.

Before I resume my seat, I congratulate and express my thanks to the Central Government, specially to the Prime Minister, the Aviation Minister and the Finance Minister for sanctioning a long-pending demand of Kerala to build an aerodrome near Calicut. I again request them to kindly expedite the construction to start during April itself. Thank you.

SHRI T. BASHEER (Kerala): Madam, I support the Statutory Resolution moved by the hon. Minister of Home Affairs. Now, once again, Kerala is under the President's Rule. Of course, the President's Rule is not a desirable thing. But there was no other option as the political situation developed in Kerala. The Governor had no other way but to advise dissolution and early elections. So, I welcome the decision and I congratulate the Governor. As you are aware, Madam, the democratic parties tried their best to avoid the Presidential Rule. That is the reason why they wanted to form an alternative Government after the fall of the Nayanar Ministry.

Madam, much has been said here about the number of Members. There were 71 Members favouring the formation of the Ministry when Karunakaran was invited to form the popular

Government. Everybody knows it. The Speaker, before his election to the office of Speaker was a Member of the Congres (Antony Group) Legislature Party, and he was for such a Government. And 70 other Members were also for the formation of a popular Government. So, the Governor's action in inviting Mr. Karunakaran to form a popular Government was quite justifiable. There is no doubt about it Afterwards, one Member was elected as the Speaker. On the floor also the majority of the Goevrnment was proved. It is true that the Speaker cast his vote. But it is certainly in compliance with the provisions of the Constitution. The Constitutional provision says that the Speaker or the Chairman or the person sitting as such shall not vote in the first instance but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes. So, it is absolutely in compliance with the constitutional provisions. Suppose the Speaker had not cast his vote. What would have happened? That will create a constitutional crisis and a crisis of proceedings. The

4 P.M.

architects of our Constitution envisaged such a situation and hence there is the provision of a casting vote by the Speaker. A great deal of hue and cry was made by the Opposition parties here and there on this issue. This was done only from the angle of their political affiliations and not for anything else. They demanded the resignation or suspension of the Government as the Government had to depend, according to them, on the casting vote of the Speaker. I would like to point out in this context that after the withdrawal of the support of the Indian National Congress, Antony Group, then there were only 70 supporters of the Nayanar Ministry. Then they did not resign. They tried to continue in power. They tried to cling to power. These people, who demand Karunakaran Ministry's resignation, did not resign then. Mr. Nayanar continued for some time with that much support. So, I do not understand the logic of their argument. This is something like a double standard. (*Time bell rings*). Then the Opposition parties brought a no-confidence motion against the Speaker. That motion was also lost on the floor. As the CPM and their friends lost the case on the floor, then they tried to engineer defections. It was not the ruling front engineering defections. It was the Opposition which did it. They always make a loud cry about defections and horse-trading. And, it is these people who talk most about moral principles and it is these people who engineer defections and indulge in horse-trading in Kerala. I cannot understand their logic. If someone defects to their side, it is not defection, but it is something very pious, something very revolutionary. The people know who are applying double standards in all these matters. The Karunakaran Ministry never tried to cling to power. They resigned immediately. Consequently the Assembly was dissolved and now it is clear that there will be early elections. Madam, I welcome the action of the Governor. The Governor was absolutely right. The democratic people of Kerala also appreciate the action. The CPM and their friends are afraid of elections. The democratic front is ready to go for elections. We are sure that the Democratic Front will come back with thumping majority. (*Time bell rings*). The people of Kerala had the bitter experience of the Marxist rule. The Marxist party has proved that they are not concerned with the welfare of the people or the interests of the State. Their only concern is the interest of their party. Beyond that they care for nothing. (*Time bell rings*).

Madam, the law and order situation was in peril during the Nayanar Ministry. They tried to use the police for their political purpose. That naturally caused denial of justice to the common people. The CITU people took law and order in their hands. They are made by the party non-

[Shri T. Basheer]

official policemen in the State. The various sections of the society, the small agriculturists, small shopkeepers, middleclass people were harassed by the CITU people. The hands of police were tied up.

The murder politics of CPM shed blood in Kerala. Many Left Democratic Front partners in the Government warned against this disaster and demanded strong impartial action. Even, no less a person than Sri P. K. Vasudevan Nair, former Chief Minister and the CPI leader accused and charged the CPM and the Home Minister on the floor of the House itself. His many party friends were also attacked and murdered by CPM workers.

I would like to say that it is an interesting paradoxy that he and his party are still with CPM. I hope that the spirit of Varanasi will be able to give Moksha to CPI from CPM.

We were a party to the Marxist Left Democratic Front. From our experience I would like to say that the CPM is neither democratic nor progressive.

We welcome the elections and we will definitely win the elections and would come back to power, and I can say that these elections will prove a Waterloo to the CPM. Thank you.

श्री शिवचन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने क ा कि अब क्या करें, अब हो गया । उस के लिये कोई रास्ता नहीं बता रहे हैं । अब तो हो चुका। अब करें क्या । मेरे मोशन पर बोलने के बाद उन्होंने सवाल किया कि अब करें क्या । अब तो लग गया वहां पर, अब कोई रास्ता बतलाइये उससे निकलने का । उन्होंने मुझ से कहा कि रास्ता तो बताया नहीं । वे खुद कहते हैं लगाना तो शुरू में चाहिए था , करणाकरण की सरकार के वक्त लग जाना चाहिए था। मेरा कहना है कि मान लीजिये कि यहां पर आप विदड्रा कर लेते हैं और कांस्टीट्यूशनल सफाई के लिये हम इस को गिरा देते हैं, आपके प्रस्ताव को, स्टेट्यूटरी रेजोल्यूशन को गिरा देते हैं, तब ? या आप विदड्रा कर दें और क्योंकि लोक सभा के अन्दर पास कर दिया गया है इस लिये यह दो महीने तक वैलैड रहेगा । यहां से होने के बाद दो महीने तक रहेगा । हम लोगों की वजह से दो महीने बाद आप लोगों को मौका मिलता है कि दो महीने के बाद चुनाव करा दें । इसको दुनिया देखेगी, भारत देखेगा कि लोक सभा में गलती हुई और राज्य सभा में आते-आते आपने गलती को महसूस किया कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना जनतंत्र पर कुठाराघात करना है, प्रहार करना है, सारा लौजिक, सारा दर्शन, प्रजातंत्र का जो है उसे खत्म करना है, । हम सब चाहते है कि जल्दी से जल्दी वहां पर चुनाव हों । यह मानी हुई बात है कि जनता उसका फैसला कर देगी, करके रहेगी यह भी आपको पता चल जायेगा कि जनता क्या फैसला करती है । दोनों बातें होगीं । जैसा आपने कहा कि लग गया है मैं कहता हूं कि वहां पर विदड्रा कर लीजिये । दो महीने तक रहेगा और वहां दो महीने तक चुनाव हो जायेंगे उस के बाद सरकार बनेगी । लेकिन आप ऐसे प्वाइंट से घबराते हैं कि विदड्रा किया तो उलट जायेगा । इस लिये इस को रहने देना चाहते हैं । आपको मालूम है कि आपकी पूरी कोशिशों के बाद भी, आपने पूरी कोशिश इमरजेंसी में की जनतंत्र को खत्म करने की, लेकिन भारत की जनता जनतंत्र का खात्मा बरदास्त नही कर सकती, यह बात आप गांठ बांध कर रख दें । भारत की पब्लिक इनहरेंन्ट कमिटिड है, टू दि डैमोक्रेसी और आपके प्रयास बीच बीच में इमरजेंसी और हिटलरवाद के बदोलत होते

रहे लेकिन यहां प्रजातंत्र का खात्मा नहीं हुआ और न होगा। केरल में लगा गुस्सा बहुत लम्बा है। 1952 से चला आ रहा है, उस में अब जाने की जरूरत नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (डा० श्रीमती नाजमा हेपतुल्ला) : आप किस्सा कह रहे हैं या गुस्सा कह रहे हैं ?

श्री शिव चन्द्र झा : मैं गुस्सा अर्थात् एंगर कह रहा हूं क्योंकि वहां सोशलिस्ट सरकार का उदय हुआ तो उनकी भवें तन गई कि यह सोशलिजम की ओर बढ रहे हैं। केरल की जनता अभी भी सोशलिस्टों के लिये डेडीकेटिड है लेकिन आप दिल से नहीं चाहते मुंह से आप चाहें जो कुछ कह दें। आप हकूमत करना चाहते हैं लेकिन जो विकास हो रहा है वह हम देख रहे हैं कि वहां पर हम को आप ले जा रहे है। इसलिये आपका यह पाइन्ट हम को जोरदार नहीं मालूम होता है। आपने महसूस किया कि देर से सही लेकिन आप भी चाहते थे लेकिन आप यदि आज विदड्रा कर देते तो देश देखेगा कि आपने एक गलती की उसको आपने यहां पर महसूस किया और यहां पर उस में सुधार कर दिया। जैसे मंसूरी के प्रोबेशनर के लिये पहले आप रिफारमैटरी अप्रोच लेने जा रहे थे और फिर 12 बजते-बजते आपको ज्ञान आ गया तो आपने इस प्रोबेशनर को हटा दिया। देर से सही लेकिन जब तक हाउस में आप स्टेटमेंट दे तब तक आपने एक कदम उठाया जिससे देश को रिलीफ की सांस मिली देश के लिये। यह एक भ्रष्टाचार का काम हो रहा था। तो इस लिये आपने गलती वहां तक की लेकिन यहां पर कोई गलती नहीं की। देश देखगा हम लोग स्वागत करेंगे। हो गया मैं मानता हूं, आप दो महीने के अन्दर निष्पक्ष चुनाव वहां पर करायें। दूसरी बात यह है कि इस बिल को जड में जो है वह डिफेक्शन है। डिफेक्शन को रोकने के लिये कानून आप बनायें। जनता सरकार के समय में वह आ रहा था, नहीं हो सका। जनता सरकार ने बहुत से काम नहीं किये तो आप ही कर दीजिये। आप ही कर दें, हम आपका स्वागत करेंगे। इस तरह डिफैक्शन को रोकने के लिये आप कानून लाय। बेहतर तो यह होगा, मेरा सुझाव यह है कि यदि वन सिक्सथ वोटर किसी एरिया के यदि रिटर्निंग अधिकारी को लिख कर दे दें कि हम अपने प्रतिनिधि को रिकाल करते है जिसने डिफेक्ट किया है। तो आप इस प्रकार से रिकाल का प्रावधान कर दें। जिस प्रकार किसी चुनाव में वन सिक्सथ से कम वोट मिलने पर उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। उसी प्रकार यदि वनसिक्सथ वोटर लिख कर देंगे तो आटोमैटिकली इलैक्शन वाइड ही जायेगा। इस लिये यदि आप इस प्रकार से कानून बनाते है तो जनतंत्र की गाडी ठीक तरह से चल सकेगी। याद रखिये पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जनतंत्र के पक्ष में अपनी किताब मार्डन रिव्यू में लिखा था उन्होंने कहा था देश की जूलियस सीजर नही चाहिए देश को डैमोक्रेसी चाहिए। जूलियस सीजर लाइक कांग्रेस का प्रेसीडेंट नही होना चाहिए। उन्होंने अपने ही खिलाफ लिखा था जो बाद में जोन गुन्थर ने भेद खोला तो आप बहकें नहीं। यह जो काम आज हो रहा है केरल में, जो आप सीधा प्रहार कर रहे हैं इस को हम बर्दास्त नहीं करेंगे। यहां पर ईंट से ईंट बजा देंगे आपके रिजोलूशन के खिलाफ।

ज्ञानी जैल सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे दोस्तों ने, आनरेबल मैम्बर साहेबान ने अपने विचार इस प्रस्ताव पर खुल कर दिये हैं। बहुत सी ऐसी समस्यायें, कुछ शंकायें और कुछ भ्रम थे उनकी निवृत्ति भी मैम्बर साहेबान ने

[ज्ञानी जैल सिंह]

खुद ही कर दी है । जो हमारे मैम्बरों को उत्तर मुझे देना चाहिए था वह भी इसी हाउस में बहुत से विद्वान मैम्बरों ने उसका उत्तर दे दिया । मेरे ख्याल में अब कोई ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती मगर झा साहब ने अपना जवाब देते हुए एक गलती की है । वह पैंने जो बात कही शायद मैं उनको समझा न सका मेरा ख्याल है कि रिकार्ड में पढ लीजिये मैंने यह कहा था मने अब यह राष्ट्रपति राज लागू होने का डिक्लेरेशन हो गया है और जो इनका रिजूलेशन है वह यह है कि 'in relation to the State of Kerala, be revoked'. यानी हम जो पास करवाना चाहते हैं वे कहते हैं कि इसको रद्द कर दें । हम तो पास इसलिए करवाना चाहते हैं कि दो महीनों के अंदर इलेक्शन न भी हो सके तो कम से कम 6 महीने की मियाद जो है, कानून के मुताबिक, कांस्टीट्यूशन के मुताबिक है, होनी चाहिए । लेकिन वे कहते हैं कि रिवोक कर दें । अब कोई मुझे समझाइये कि अगर मैं इनकी बात मान लूं, क्योंकि मैंने उस कन्टेक्स्ट में कहा था कि सुधार के बाद किया, फिर आप ने बदल दिया। तो एक ऐसी बात थी, वह एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिजन था और मेरे अधिकार में था। मैंने बदल कर ठीक किया या गलत किया, आप को प्रशंसा करनी चाहिए थी कि हमारी बात को मान लिया । लेकिन आप शराफत को कमजोरी न समझिए। मैं समझता हूं कि इस बात का जवाब आप के पास नहीं है कि आज राष्ट्रपति की तरफ से जो प्रोक्लेमेशन हुआ है उसको लागू न किया जाय । मैं इसको वापस ले लूं तो फिर वहां राज किसका होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलायेगा, चुनाव कौन करवायेगा, कैसा रास्ता होगा। मैं समझता हूं कि आपका जो काम था आपने कर लिया । आपने तकरीर करनी थी कर ली . . . . (**व्यवधान**) आपने जो हमारे डिसीजन के खिलाफ कहना था कह लिया और इसके बाद आप इस रिजोल्यूशन को न दें। अगर आप चाहते है तो करें। लेकिन यह कैसा मजाक हो सकता है कि गृह मंत्री लोकसभा में एक प्रस्ताव पास कर लाये और फिर वह राज्य सभा में आकर उसको वापस ले लें । यह कोई अक्ल की बात नहीं हो सकती, यह मैं कभी नहीं करुंगा। इनका यह ख्याल है कि इमरजेंसी के बाद भारत की जनता ने जवाब दिया लेकिन भारत की जनता ने जो जवाब दिया था उसका क्या परिणाम निकला, यह आपको मालूम है और उस जवाब के बाद हमारा सफाया नहीं हुआ, हम तो है, "कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी" आप नहीं है। हमें तो कहीं दिखाई नहीं देते कि आप कितने टुकड़ों में बिखर गये ।

जब पहले 1980 में सेशन हुआ था उस वक्त मैंने कहा था कि जो वह गाना है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए . . . अब वह गाना बदल गया है, "इस दल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा" यह हालत है आपकी। भारत की जनता पछता रही है कि ऐसे लोगों को राज दिया जिनको राज करने की अक्ल नहीं थी (**व्यवधान**) न आपका अनुशासन था, न आपको शासन करने की अक्ल थी (**व्यवधान**)

श्री शिव चन्द्र झा : हम चाहते है आप कभी वहां रहें, कभी हम वहां रहे । फिर कभी आप रहें, कभी हम रहें . . (**व्यवधान**) यह नही है कि हम रहें। यही तो फर्क है हम दोनों में . . . (**व्यवधान**)

ज्ञानी जैल सिंह : झा साहब अगर मेरे से पूछे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि झा साहब को मौका दो परमात्मा कि वे भी मिनिस्टीरियल बेंचों में आवें। मैं आपका बुरा

चाहने वाला नहीं हूं लेकिन . मैं तो सिर्फ इतनी सी बात आपको कहता हू कि भारत की जनता जो फैसला करती है उसको सुधार भी लेती है। हालांकि आपको पांच साल देखने चाहिये थे लेकिन वे पांच साल इंतजार नही कर सके, चूंकि आपमें शासन करने की योग्यता नही थी, न ही अनुशासन था आपका। अब हमारा तो कोई कसूर नही। हमने आपको निकालकर वहां नहीं फेंका। यह तो आप खुद ब खुद चले गये और उसके लिये आप अपने दिल को टटोली, दूसरों से कहने का क्या फायदा और यह पढ़ा करो कि "दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से, इस घर को आग लग गयी, घर के चिराग से"

खैर मेरी भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के मेम्बर साहिबान से बड़ी हमदर्दी है, उनको चाहिये था कि वेलकम करते। वाईस चेयरमैन साहिबा, अब जो पार्टियां हैं, 12 पार्टियां है, उन 12 पार्टियों में से लोक दल और भारतीय जनता पार्टी के केरल में जीरो है। अब जीरो वाले कहते है, आपने गलत किया। जब नहीं किया था तो कहते थे क्यों नहीं किया। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ एग्री नही करते। मैं माधवन नायर जी से जरुर हमदर्दी करता हू। चूंकि शायद वह रिटर्न हो जाते, अब वह नही आ सकेंगे, इसके लिये भगवान उनको इस भावी को बर्दाश्त करने का बल दें।

हमारे मुस्लिम लीग के आनरेबल मेम्बर साहेबान ने जो बातें कह दीं, उनकी वजह से भी और रामचन्द्रन जी की वजह से भी, हमारे मिस्टर घोष जी भी बैठे है, उनकी वजह से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे प्रश्न रहे नहीं जिसका जवाब मेम्बरों को नहीं मिला और अब यह मौका मिला पहली बार राज्य सभा मे और यहां से ही नहीं, वहां से ही जवाब मिल गया, आने की जरुरत नहीं पड़ी।

आखिर में जो आनरेबल मेम्बर ने स्पीच दी, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया सफाई कर दी, सब बातें कीं। मैं तो अब यह, चाहता हूं कि वह प्रश्न करेंगे कि इलैक्शन कब कराओगे ? उचित समय पर। लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाये।

आप इस मामले में हमे मिलवर्तन दें और इस बात के लिये तैयारी करें कि इलैक्शन लड़ना है और आप तो शायद जनता पार्टी के मेम्बर है-- क्योंकि जनता भी तो दो-तीन है ना।

श्रीमती हामिदा हबीबुल्लाह (उत्तर प्रदेश) : कौनसी जनता ?

ज्ञानी जैल सिंह : नही, मैं जानता हू जनता को। इनके नेता को हम जानते है। नेता बड़े अच्छे है, बहुत दूर दृष्टि वाले, मुझे बहुत हमदर्दी होती है क्योंकि हमारे साथी है, बहुत बड़े है, उनसे बातें सीखते रहे, आखिरी उमर में क्या हो गया, यह मैं नही कह सकता।

खैर हमदर्दी करते हुए मै आपसे यही कहना चाहूंगा कि असेम्बली के अंदर आपका नाम जीरो है। आपका कोई मेम्बर वहां नही है। इसलिये आप दिल में जरुर खुश हुए होंगे कि मौका मिलेगा, शायद एकाध मेम्बर बन जाएं। हो सकता है क्योंकि इतनी पार्टियों में से कुछ न कुछ तो होगा ही।

तो मैं, उपसभाध्यक्ष महोदया, आपके थ्रू प्रार्थना करूंगा आनरेबल मेम्बर साहबान कि वे इस मामले में वोट न कराएं और वायस वोट की भी जरूरत नहीं है। वह अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें और खुशी-खुशी इसको कबूल करें।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): I shall first put the Motion moved by Shri Shiva Chandra Jha to vote. The question is:

"That this House recommends to the President that the Proclamation issued by the President on the 17th March, 1982, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Kerala, be revoked."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): I shall now put the Statutory Resolution to vote. The question is:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 17th March, 1982, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Kerala."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NIJMA HEPTULLA): We will now go to the next item on the agenda.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: On a point of order. I am insisting 'Ayes' have it on my Motion. Either by voice vote or by standing...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): We have finished Kerala. We are going now to Assam. Mr. Dinesh Goswami.

श्री शिव चन्द्र झा: जो सदन की परम्परा है.... (**व्यवधान**) यह चलाइयेगा.. (**व्यवधान**)

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): Madam, Vice-Chairman, on a point of order. If Mr. Jha insists that there should be voting, we will have to go for voting. I am submitting to you, Madam. But I will request Mr. Jha, let him not insist when the entire Opposition is not insisting.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Whether by standing or by voice vote. *(Interruptions)*.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): We put it to vote.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: There must be voting here. नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होता है। वह एक परम्परा चलाइयेगा . . . (**व्यवधान**) हम लोग यहां .... (**व्यवधान**

I am not withdrawing my Motion. I stand by it.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): We put it to vote.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: I wanted a division.

हम लोगों में यहीं, दो-दो तीन-तीन आदमियों ने लिख कर दिया है । 3 आदमियों के कहने पर भी वोटिंग हुई है । यह परंपरा रही है। पांच-दस मिनट में कुछ बिगड़ने का नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष (डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला) : मैं समझ गई। आप बैठेंगे।

श्री शिव चन्द्र झा: आप डिविजन कराइये।

उपसभाध्यक्ष (डा० श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला) : झा साहब, आप के मोशन पर वोटिंग हुई, आपका मोशन गिर गया, वह निगेटिव हो गया। आपने उसी समय अगर डिविजन मांगा होता तो डिविजन होता। आप ने डिविजन मांगा नहीं।

श्री शिव चन्द्र झा : नहीं, शुरू से हमारी मांग रही डिविजन की।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): Now the decision is taken. We now go to Assam. Mr. Dinesh Goswami.

(I) MOTION SEEKING REVOCATION OF THE PROCLAMATION ISSUED BY THE PRESIDENT ON THE 19TH MARCH, 1982 IN RELATION TO THE STATE OF ASSAM.

(II) STATUTORY RESOUTION SEEKING APPROVAL OF THE PROCLAMATION ISSUED BY THE PRESIDENT ON THE 19TH MARCH, 1982 IN RELATION TO THE STATE OF ASSAM.